सांध्य दैनिक

श्रीकंचनपथ

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534
डाक पंजीयन क्रं.-छ.ग./ दुर्ग /94/2023-25

वर्ष- 15 अंक - 153 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, शनिवार 16 मार्च 2024 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

खास-खबर

30 नगरीय निकायों के लिए 112 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत

रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के 30 नगरीय निकायों के लिए 14वें एवं 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत कुल 112 करोड़ दस लाख 51 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। इनमें 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 30 नगरीय निकायों के लिए कुल 111 करोड़ 88 लाख एक हजार रुपए तथा 14वें वित्त आयोग के तहत खरौद नगर पंचायत के लिए 19 लाख 38 हजार रुपए और नई लेदरी नगर पंचायत के लिए तीन लाख 12 हजार रुपए की राशि शामिल हैं। नगरीय निकायों में विकास कार्यों में तेजी लाने उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने ये राशि मंजूर की है। उन्होंने गुणवत्ता एवं समय-सीमा का ध्यान रखते हुए इन राशियों से प्रस्तावित कार्यों को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत भिलाई-चरोदा नगर निगम के लिए सात करोड़ 71 लाख 37 हजार रुपए, बिलासपुर नगर निगम के लिए आठ करोड़ 90 लाख 86 हजार रुपए, कवर्धा नगर पालिका के लिए 71 लाख 39 हजार रुपए, सरायपाली नगर पालिका के लिए एक करोड़ 53 लाख 78 हजार रुपए, बागबहरा नगर पालिका के लिए आठ लाख 33 हजार रुपए, लोरमी नगर पंचायत के लिए 98 लाख रुपए, डौंडीलोहारा नगर पंचायत के लिए 73 लाख 52 हजार रुपए, दुर्ग नगर निगम के लिए तीन करोड़ 69 लाख 53 हजार रुपए, रायगढ़ नगर निगम के लिए सात करोड़ 11 लाख 75 हजार रुपए, राजनांदगांव नगर निगम के लिए चार करोड़ 20 लाख 62 हजार रुपए, बलौदाबाजार नगर पालिका के लिए 45 लाख सात हजार रुपए, नई लेदरी नगर पंचायत के लिए 52 लाख रुपए, उतई नगर पंचायत के लिए 32 लाख 85 हजार रुपए और चिरमिरी नगर निगम के लिए चार करोड़ 37 लाख 94 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। विभाग द्वारा 15वें वित्त आयोग के तहत झगराखंड नगर पंचायत के लिए 12 लाख रुपए, मुंगेली नगर पालिका के लिए 18 लाख रुपए, मनेंद्रगढ़ नगर पालिका के लिए साढ़े 16 लाख रुपए कोटा नगर पंचायत के लिए 37 लाख 24 हजार एवं धमतरी नगर निगम के लिए 11 करोड़ 48 लाख 32 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं।

धुआंधार प्रचार में जुटी सरोज,ज्योत्सना पर तंज, कांग्रेस को बताया डूबती नाव

श्रीकंचनपथ न्यूज़ डेस्क

कोरबा। कोरबा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सरोज पाण्डेय ने धुआंधार प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। सरोज अपनी आक्रामक छवि के अनुरूप प्रचार कर रही हैं। कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज बताते हुए सुश्री पाण्डेय ने वर्तमान सांसद ज्योत्सना महंत पर भी तंज कसा है। उन्होंने भरोसा जताया है कि मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सुश्री पाण्डेय ने देश के अभूतपूर्व विकास और आत्मसम्मान के लिए भाजपा को वोट देने की अपील भी की।

कोरबा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडेय धुआंधार चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। अपनी जीत पक्की करने के लिए सुश्री पाण्डेय गौरैला पेंड्रा मरवाही के दौरे पर पहुंचीं। पांडेय ने कहा कि पीएम मोदी तीसरी बार दिल्ली की गद्दी पर बैठें, इसके लिए आप लोग वोट करें। निर्वाचन आयोग आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है, लेकिन इससे पहले ही कोरबा में चुनावी माहौल गरमा गया है।

जेब में पैसे डालने का किया काम

मरवाही विधानसभा में प्रचार के दौरान सरोज पांडेय बरौर मंदिर भी पहुंचीं। बरौर मंदिर में सरोज पांडेय ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। महिला कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान सरोज पांडेय ने कहा कि मोदी जी आपके लिए कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं। महतारी वंदन योजना से लेकर किसान सम्मान निधि तक आपकी आय को बढ़ाने का साधन है।

जनता देगी जवाब

चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कोरबा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडेय धुआंधार प्रचार में जुट गई हैं। जीपीएम पहुंचीं सरोज पांडेय ने कहा कि पांच सालों में कोरबा लोकसभा सीट पर विकास का काम नहीं हुआ। बीजेपी की केंद्र में सरकार बनते ही विकास के काम तेजी से होने शुरु हो जाएंगे। पांच सालों में यहां की सांसद ज्योत्सना महंत ने विकास के कामों से मुंह मोड़ लिया था। जनता वोट से अब इसका जवाब देने के लिए तैयार है।

5 साल का हिसाब दे ज्योत्सना

कोरबा लोकसभा क्षेत्र में विकास नहीं होने पर सरोज पांडेय ने कहा कि पांच साल से यहां की सांसद ज्योत्सना महंत हैं। इसके पहले भी कांग्रेस के सांसद यहां से रहे। सांसद को पांच करोड़ की सांसद निधि मिलती है। पांच करोड़ में कितना विकास यहां हुआ ये हर कोई जानता है। जनता अब इस चुनाव में कांग्रेस से उसका हिसाब मांग रही है। चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठा रही है, उससे उसे कुछ हासिल नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के पास चुनावी मैदान में उतरने का कोई नैतिक मुद्दा नहीं है।

कांग्रेस ने तय कर लिए 5 प्रत्याशी बस्तर से बैज को मिला अभयदान

श्रीकंचनपथ न्यूज़ डेस्क

रायपुर। छत्तीसगढ़ की बाकी बची 5 सीटों पर कांग्रेस ने नाम तय कर लिए हैं। अब तक इन 5 सीटों पर असमंजस बना हुआ था। पार्टी ने पूर्व में 6 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए थे। लेकिन 5 नामों को लेकर आमराय नहीं बन पाने की वजह से सीईसी ने दूसरे राज्यों की ओर रूख कर लिया था। अब खबर आ रही है कि बाकी बची सीटों के लिए नामों को अंतिम रूप दे दिया गया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने दिल्ली से लौटने के बाद हाल ही में कहा था कि नामों को लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं है और जल्द ही नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। पता चला है कि कांग्रेस आज या कल इन प्रत्याशियों के नाम घोषित कर सकती है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा के 11 सीटें है। जिसमें से 6 सीटों के प्रत्याशियों के नाम पहले ही घोषित कर दिए गए थे। जबकि बाकी बची पांच सीटों को लेकर असमंजस बना हुआ था। बताया गया है कि अब वह ख़त्म हो गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पांच सीटों पर अब नाम तय हो गए है। बताते हैं कि सीईसी में सबसे ज्यादा चर्चा बस्तर सीट को लेकर हुई है। यहां से वर्तमान में दीपक बैज सांसद हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। पार्टी के नेता चाहते थे कि उनकी जगह किसी नए चेहरे को टिकट दी जाए और बैज स्वयं प्रदेशभर में चुनाव अभियान की कमान संभालें। लेकिन अब खबर आ रही है कि बस्तर लोकसभा सीट से दीपक बैज के नाम पर अंतिम मुहर लगा दी गई है। कांकेर सीट से बिरेश ठाकुर को प्रत्याशी बनाए जाने की खबर है।

इन नामों को किया गया फायनल

बिलासपुर लोकसभा सीट से नए प्रत्याशी के तौर पर विष्णु यादव के नाम तय किया गया है। बता दें इस सीट से अचानक ही भिलाई के विधायक देवेन्द्र यादव का नाम भी चर्चा में आया था, लेकिन कई कारणों से उनके नाम को आगे बढ़ाने से परहेज किया गया। वहीं कांग्रेस पार्टी ने सरगुजा सीट से शशि सिंग के नाम पर मुहर लगा दी हैं। रायगढ़ से महिला प्रत्याशी के रूप में मेनका सिंग का नाम सामने आया है। कांकेर से बिरेश ठाकुर और बस्तर सीट से दीपक बैज के नाम को फायनल किया गया है।

वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन 23 मार्च तक एमपी, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान दौरे पर

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर के 6 दशक बाद नाई समाज से रिकेश सेन के वैशाली नगर विधायक बनने पर देश भर में नाई समाज में हर्ष की लहर है। इसी वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की है। वैशाली नगर विधायक का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा में उन्हें टिकट देने का निर्णय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच का ही परिणाम है।

विधायक रिकेश सेन ने कहा कि पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व दिलाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की दूरदर्शिता हमेशा से रही है जिससे पिछड़ा वर्ग में गजब उत्साह है। इसी तारतम्य में नाई समाज द्वारा अनेक राज्यों में समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली सामाजिक हस्तियों और जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। इन आयोजनों में बतौर अतिथि शिरकत करने वैशाली नगर विधायक 16 मार्च से 23 मार्च तक गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान और हरियाणा राज्य के प्रवास पर रहेंगे। यह सम्मेलन मध्यप्रदेश के इंदौर, गुजरात के सूरत, राजस्थान के जयपुर और हरियाणा के सोनीपत में होंगे।

छत्तीसगढ़ में 4 आईएएस का प्रभार बदलाः संजय अलंग को बिलासपुर कमिश्नर का अतिरिक्त चार्ज

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने 4 आईएएस अफसरों के विभाग बदले हैं। रायपुर संभाग के कमिश्नर संजय अलंग को बिलासपुर कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। शिखा राजपूत तिवारी को वन विभाग के सचिव का जिम्मा मिला है। शारदा वर्मा के पास सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार था उन्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त किया गया है। कुंदन कुमार को गृह निर्माण मंडल का आयुक्त बनाया गया है।

आयुष्मान अस्पताल फिर वेंटिलेटर पर

श्रीकंचनपथ

स्वास्थ्य किसी भी देश के विकास के महत्वपूर्ण मानकों में से एक है। स्वास्थ्य का अधिकार वैसे तो मौलिक अधिकार नहीं है, पर संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। संविधान के विभिन्न प्रावधान बड़े पैमाने पर जन स्वास्थ्य से संबन्धित हैं। जनता के लिए यह स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना केंद्र और राज्य सरकारों के मूल उत्तरदायित्व में शामिल है। सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना भी सरकारों का निहित दायित्व है। आयुष्मान भारत योजना, इसी दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। योजना के तहत पीड़ित को श्रेष्ठ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस तक पहुंच को इतना आसान कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जरूरत पड़ने पर अपना राशन कार्ड लेकर किसी भी आयुष्मान अस्पताल तक जा सकता है और वहां निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं हासिल कर सकता है। योजना जनता के लिए चाहे जितना भी आसान हो, सरकार और उसके कार्पोरेट शुभचिन्तकों के लिए यह उतना ही बड़ा सिरदर्द है। देश में स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाली कुल 30 बड़ी कंपनियां हैं। इसके अलावा भी कुछ लोग स्वास्थ्य की फंडिंग करते हैं। आयुष्मान भारत योजना इन सभी के लिए चुनौती बनी हुई है। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को माध्यमिक और तृतीयक (टर्शरी) स्तर की चिकित्सा के लिए 5 लाख रुपए तक की सुविधा दी जाती है। एपीएल कार्डधारकों के लिए 50 हजार रुपए तक के इलाज की सुविधा इस योजना के तहत दी जाती है। पर यह योजना का केवल आधा सच है। बीपीएल और एपीएल कार्डधारकों को लगता है कि वे अस्पताल जाएंगे और 5 लाख या 50 हजार रुपए तक की चिकित्सा सुविधा हासिल कर लेंगे। ऐसा नहीं है। प्रत्येक बीमारी और उसके इलाज के लिए पैकेज दरें निर्धारित हैं। अर्थात बीमारी के अनुसार यह तय किया जाता है कि इलाज के लिए कितने पैसे मिलेंगे। जब से आयुष्मान योजना आई है बड़ी कंपनियों के लिए स्वास्थ्य बीमा बेचना मुश्किल हो गया है। जिस क्षेत्र में कभी बीमा अभिकर्ताओं ने लाखों रुपए की कमाई की थी और आए दिन कंपनियां करोड़पति अभिकर्ताओं की सूची जारी कर उन्हें सम्मानित किया करती थीं, उन्हें अब नए अभिकर्ता मिलने मुश्किल हो गए हैं। जानकारों का मानना है कि आयुष्मान योजना की कठिन शर्तों के पीछे इन्हीं बीमा कंपनियों की साजिशें हैं। यदि आयुष्मान योजना में दिक्कतें आती हैं तो टर्शरी लेवल की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाले अस्पताल योजना से अलग हो सकते हैं। आयुष्मान योजना की भुगतान विसंगतियों का शिकार होकर छोटे अस्पताल और नर्सिंग होम अपनी मौत खुद ही मर जाएंगे। इससे बीमा कंपनियों की राह कुछ आसान हो जाएगी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों की क्लेम बकाया राशि 12 सौ करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने वाली है। इस दौरान फिर भुगतान रुक जाएगा।

संपादकीय

पारदर्शिता जरूरी

इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरे देश में चर्चा स्वाभाविक है और इसी कड़ी में देश के सर्वोच्च न्यायालय के प्रयासों और सबसे बड़े सरकारी बैंक-स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फिर मिली फटकार को देखा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को एसबीआई को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा है। वास्तव में, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की जो सूची पोस्ट हुई है, उसे अधूरा माना जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा, यह तो पता चल रहा है, लेकिन इससे किसे लाभ हुआ या उसका किस पार्टी ने लाभ लिया, इसकी जानकारी नहीं मिल रही है। कोई अल्फान्यूमेरिक नंबर है, जो सूची के साथ शामिल नहीं है। अब सर्वोच्च न्यायालय की फटकार के बाद एसबीआई को अपनी सूची को और स्पष्ट करना होगा। उसे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप पहले ही कार्रवाई करनी ही चाहिए थी, ताकि उस पर उंगली न उठती। इसमें कोई दोराय नहीं कि इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत राजनीतिक चंदे के लेन-देन को पारदर्शी बनाने के लिए की गई थी। यहां पारदर्शिता का सीधा अर्थ है कि लोगों को चंदे के बारे में पूरी सूचना होनी चाहिए। किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितने पैसे दिए हैं? जब एक बार पैसे के लेन-देन के बारे में साफ तौर पर पता चल जाता है, तब लोग यह आकलन करने की स्थिति में होते हैं कि पैसा क्यों लिया गया होगा या चंदा क्यों दिया गया होगा? दरअसल, चंदे की पूरी व्यवस्था ही विवेक पर निर्भर करती है। देने वाला अपने विवेक से देता है और जाहिर है, जो करोड़ों रुपये देगा, वह कुछ फायदे लेने के बारे में भी जरूर सोचेगा। आज के महंगे और पूंजीवादी दौर में यह सोचना बहुत भोलापन होगा, अगर हम यह सोचें कि अब तक करोड़ों रुपये का चंदा स्वेच्छा से लिया और दिया जाता रहा है। बहरहाल, जहां तक एसबीआई या किसी अन्य संस्था का सवाल है, तो हर हाल में पारदर्शिता के पक्ष को ही मजबूत किया जाना चाहिए। लोकतंत्र में किसी संस्था को जरूरी सूचना छिपाने का हक नहीं होना चाहिए। केवल देश की सुरक्षा से संबंधित दस्तावेजों की ही गोपनीयता सुनिश्चित रहनी चाहिए। बाकी तंत्र का कोई भी हिस्सा अगर किसी तरह का लेन-देन कर रहा है, तो इसके बारे में लोगों को पूरी सूचना होनी ही चाहिए। मतलब, एसबीआई को देश और उसके लोकतंत्र में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, अगर उसका व्यवहार कहीं से भी इस संदर्भ में उदासीन दिखे, तो चिंता होती है। पहले भी अनेक मौके आए हैं, जब हमने इस बैंक का पक्षपाती रवैया देखा है। शीर्ष अदालत की पीठ ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और वकील प्रशांत भूषण की दलीलों पर ध्यान दिया है कि एसबीआई द्वारा चुनावी बॉन्ड के अल्फान्यूमेरिक नंबरों का खुलासा नहीं किया गया है। अब एसबीआई को अपनी विश्वसनीयता बहाल करने की दिशा में गंभीरता से काम करना होगा। यह ध्यान देने की बात है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की गहरी तफ्तीश के लिए अब एसआईटी के गठन की मांग हो रही है। इसका सीधा-सा मतलब है कि यह विवाद जल्दी नहीं सुलझने वाला। कुल मिलाकर, एसबीआई और अन्य सभी वित्तीय संस्थाओं को सावधान हो जाना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड पर आया फैसला एक नजीर है। अब सबको कानून सम्मत पारदर्शिता के लिए काम करना होगा। एसबीआई पर देश के लोगों का काफी भरोसा रहा है, उसकी साख को और चोट न पहुंचे, इसकी चिंता उसे ही करनी है।

> “ पहले भी अनेक मौके आए हैं, जब हमने इस बैंक का पक्षपाती रवैया देखा है। शीर्ष अदालत की पीठ ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और वकील प्रशांत भूषण की दलीलों पर ध्यान दिया है कि एसबीआई द्वारा चुनावी बॉन्ड के अल्फान्यूमेरिक नंबरों का खुलासा नहीं किया गया है। अब एसबीआई को अपनी विश्वसनीयता बहाल करने की दिशा में गंभीरता से काम करना होगा।

किसानों की बात सुनें

फिलहाल उम्मीद करनी चाहिए किसान संगठनों के प्रति सरकार के रुख में बदलाव सिर्फ चुनावी कारणों से नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हुआ, तो फिर यही कहा जाएगा कि वर्तमान के टकराव को कुछ समय के लिए महज टाला भर गया है।

यह स्वागतयोग्य है कि दिल्ली पुलिस ने संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) को रामलीला मैदान में महापंचायत लगाने की इजाजत दी। इसे प्रशासन के रुख में एक बड़े बदलाव के रूप में लिया जाएगा। इस सिलसिले में यह याद करना उचित होगा कि 2020 में भी किसान संगठन तीन कृषि कानूनों पर विरोध जताने के लिए दिल्ली आ रहे थे। मगर सरकार ने उन्हें राजधानी में प्रवेश नहीं करने दिया। नतीजा यह हुआ कि राष्ट्रीय राजधानी के तीन सीमा-स्थलों पर किसानों ने डेरा डाल दिया, जो 13 महीनों तक चला।

पिछले महीने एसकेएम से निकले एक छोटे गुट ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसान कर्ज माफी की मांग पर जोर डालने के लिए दिल्ली की तरफ कूच किया, तब उन्हें पंजाब-हरियाणा की सरहद पर स्थित शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया। वहां पुलिस ने जो सख्त कार्रवाइयां कीं, उसकी रिपोर्टिंग अब दुनिया भर में हो चुकी है। इस पृष्ठभूमि में एसकेएम को रामलीला मैदान तक जाने की इजाजत मिलना एक सुखद घटना महसूस हुई है। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करना नागरिकों का अधिकार है।

प्रशासन ने इस बार इस मूलभूत सिद्धांत को स्वीकार किया है। इससे संभावित टकराव से बचा जा सका है। साथ ही इससे वह स्थिति बनी है, जिसमें किसानों की शिकायतों और उनकी मांगों पर सकारात्मक ढंग से राय-मशविरे की गुंजाइश बनती है। अब उचित यह होगा कि किसान मजूदर महापंचायत में जो चर्चा हुई, सरकार उस पर गंभीरता से ध्यान दे। उसे लोकतांत्रिक विचार-विमर्श की भावना का प्रदर्शन करते हुए किसान और मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की पहल करनी चाहिए। किसानों की मांगों को मानने में उसके सामने क्या अड़चनें हैं, उसे वह किसान संगठनों को प्रत्यक्ष रूप से बता सकती है।

दोनों पक्षों की अपनी विवशताओं के बीच मिलन बिंदु कहां हो सकता है, अगर नजरिया सकारात्मक हो, तो उसे ढूंढना असंभव नहीं है। फिलहाल उम्मीद करनी चाहिए सरकार के रुख में बदलाव सिर्फ चुनावी कारणों से नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हुआ, तो फिर यही कहा जाएगा कि वर्तमान के टकराव को कुछ समय के लिए महज टाला भर गया है।

क्या सैनी से भाजपा के हित सधेगें?

अजीत द्विवेदी

> “ भाजपा पिछले करीब 10 साल से हरियाणा में जाट बनाम गैर जाट की राजनीति करती रही है। उसने 10 साल पहले हरियाणा सहित कई राज्यों में शक्तिशाली और सत्ता की स्वाभाविक दावेदार मानी जाने वाली जातियों को छोड़ कर दूसरी जातियों को सत्ता सौंपी। महाराष्ट्र में गैर मराठा देवेंद्र फड़नवीस, हरियाणा में गैर जाट मनोहर लाल खट्टर और झारखंड में गैर आदिवासी रघुबर दास मुख्यमंत्री बनाए गए थे। मोटे तौर पर यह राजनीति कामयाब रही है। हालांकि महाराष्ट्र और झारखंड में लगातार दूसरी बार सरकार नहीं बनी फिर भी भाजपा अपना वोट बढ़ाने और उसे बनाए रखने में कामयाब रही।

नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने को भाजपा का नायाब दांव माना जा रहा है। माना जा रहा है कि एक दांव से भाजपा ने कई लक्ष्य साध लिए हैं। अब भाजपा सरकार के खिलाफ एंटी इन्कम्बैंसी खत्म हो जाएगी। किसानों की नाराजगी दूर हो जाएगी। पिछड़ी जातियों का पूरी तरह से ध्रुवीकरण भाजपा के पक्ष में हो जाएगा और दूसरी ओर त्रिकोणात्मक लड़ाई में दुष्यंत चौटाला जाट वोटों का बंटवारा करके कांग्रेस को नुकसान पहुंचा देंगे।

लेकिन क्या सचमुच ऐसा हो जाएगा? क्या राजनीति सचमुच इस तरह एकरेखीय और इतनी ही सरल होती है कि चुनाव से पहले एक चेहरा बदल देने से पूरी राजनीति बदल जाएगी? कुछ राज्यों जैसे गुजरात और उत्तराखंड में ऐसा जरूर हुई है लेकिन उन राज्यों की राजनीति और सामाजिक संरचना दोनों भिन्न थे। हरियाणा की राजनीति उनसे अलग है। उसी तरह जैसे कर्नाटक की राजनीति अलग थी और वहां चेहरा बदलने का दांव नहीं चला। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि हरियाणा में यह नायाब दांव अनिवार्य रूप से विफल ही हो जाएगा।

बहरहाल, मनोहर लाल खट्टर लगातार नौ साल से अधिक समय से मुख्यमंत्री थे तो क्या चुनाव से पहले उनको बदल देने से उनकी सरकार के खिलाफ अगर कोई एंटी इन्कम्बैंसी थी तो वह खत्म हो जाएगी? ध्यान रहे पिछले 10 साल में जितने राज्यों में भाजपा की सरकार बनी और जो भी मुख्यमंत्री बना उनमें से किसी का कार्यकाल इतना लंबा नहीं रहा, जितना खट्टर का था। सो, उनके खिलाफ बाकी राज्यों से ज्यादा एंटी इन्कम्बैंसी स्वाभाविक रूप से बनी होगी। दूसरे, उनके कार्यकाल में दोनों किसान आंदोलन हुए, जिनके केंद्र में हरियाणा रहा।

पहले आंदोलन के समय किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए खट्टर सरकार ने जो कार्रवाई की थी उसने किसानों को बुरी तरह से नाराज किया था। दूसरे आंदोलन में भी पंजाब और हरियाणा के खनौरी और शंभू बॉर्डर पर जिस तरह से किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए या नकली गोलियों से फायरिंग हुई उससे किसान नाराज हैं। उनकी नाराजगी निश्चित रूप से सिर्फ मनोहर लाल से नहीं होगी।

भाजपा पिछले करीब 10 साल से हरियाणा में जाट बनाम गैर जाट की राजनीति करती रही है। उसने 10 साल पहले हरियाणा सहित कई राज्यों में शक्तिशाली और सत्ता की स्वाभाविक दावेदार मानी जाने वाली जातियों को छोड़ कर दूसरी जातियों को सत्ता सौंपी। महाराष्ट्र में गैर मराठा देवेंद्र फड़नवीस, हरियाणा में गैर जाट मनोहर लाल खट्टर और झारखंड में गैर आदिवासी रघुबर दास मुख्यमंत्री बनाए गए थे। मोटे तौर पर यह राजनीति कामयाब रही है। हालांकि महाराष्ट्र और झारखंड में लगातार दूसरी बार सरकार नहीं बनी फिर भी भाजपा अपना वोट बढ़ाने और उसे बनाए रखने में कामयाब रही।

इसी राजनीति के तहत पंजाबी समुदाय के मनोहर लाल को हटा कर पिछड़ी जाति के नायब सिंह सैनी सीएम बनाए गए हैं। गैर जाट चेहरा बता कर उनको नायाब दांव की तरह पेश किया जा रहा है। यह सही है कि राज्य में एक तिहाई से ज्यादा आबादी पिछड़ी जातियों की है लेकिन क्या सैनी के नाम से सब भाजपा से जुड़ जाएंगे? दूसरा सवाल यह है कि गैर पिछड़ी जातियों का क्या होगा? क्या वे भी सैनी को नेता मान कर भाजपा के इस प्रयोग को सफल बना देंगे?

यह ध्यान रखने की जरुरत है कि सैनी अगर गैर जाट चेहरा हैं तो वे गैर ब्राह्मण भी हैं, गैर दलित भी हैं, गैर गुर्जर भी हैं तो फिर ये जातियां कैसे उनके साथ जुड़ेंगी? क्या गैर जाट की भावना इतनी प्रबल है कि उसके विरोध में सारी जातियां किसी को भी नेता स्वीकार कर लेंगी? अगर बहुत सरल तरीके से यह मानें कि जिस जाति या समुदाय का व्यक्ति मुख्यमंत्री होता है उसकी जाति उसके साथ ज्यादा मजबूती से गोलबंद होती है तो फिर इसी तर्क से यह मानना होगा कि दूसरी जातियां उससे दूरी बनाएंगी।

इसलिए जाति का हिसाब कभी भी इतने सरल तरीके से काम नहीं करता है। उसके साथ कुछ और फैक्टर जोड़ने होते हैं। सैनी के प्रयोग के साथ भाजपा के पक्ष में यह बात जाती है कि पहले लोकसभा का चुनाव होना है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर होना है। इसलिए लोकसभा चुनाव में बिल्कुल निचले स्तर पर जातियों का विभाजन होने की संभावना कम है। लेकिन विधानसभा चुनाव में तस्वीर पूरी तरह से बदल भी सकती है।

यह बात समझने की जरुरत है कि अगर सत्ता के शीर्ष पर बैठा नेता अपनी जाति के वोट आकर्षित करता है तो उसकी वजह से दूसरी जातियों के वोटों में विकर्षण भी होता है। भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि चुनाव से पहले जिसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है चुनाव जीतने के बाद भी वही सीएम बनता है। गुजरात से उत्तराखंड तक यह बात दिखाई देती है।

उत्तराखंड में तो मुख्यमंत्री रहते विधानसभा का चुनाव हारने वाले पुष्कर सिंह धामी को ही सीएम बनाया गया था। इस हिसाब से हरियाणा के मतदाताओं में यह मैसेज अपने आप जाएगा कि भाजपा जीतेगी तो फिर सैनी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। यह मैसेज विधानसभा चुनाव में कई जातियों को भाजपा से दूर भी कर सकता है। ध्यान रहे जमीनी स्तर पर जातियों की गोलबंदी हमेशा एक जैसे अंदाज में काम नहीं करती है।

यह मानना भी पूरी तरह से ठीक नहीं होगा कि दुष्यंत चौटाला को अब भाजपा ने अपने से दूर कर दिया तो वे अलग लड़ कर जाट वोटों का बंटवारा कर देंगे, जो अभी लगभग पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने प्रदेश की कमान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को सौंपी है। वे 10 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जाट उनके साथ एकजुट हुए थे, जिससे कांग्रेस को 30 सीटें मिलीं। उस चुनाव में दुष्यंत चौटाला की नई बनी जननायक जनता पार्टी को 10 सीटें मिली थीं। चुनाव के बाद एक समय ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस और चौटाला की पार्टी मिल कर सरकार बना सकते हैं।

लेकिन भाजपा को केंद्र और राज्य की सत्ता में होने का लाभ मिला और उसने चौटाला के साथ मिल कर सरकार बना ली। चौटाला चार साल से ज्यादा समय तक कई महत्वपूर्ण मंत्रालय लेकर उप मुख्यमंत्री बने रहे। इसलिए अचानक अलग होकर वे भाजपा विरोधी राजनीति करते हैं तब भी भाजपा विरोधी नेता की उनकी साख नहीं बनेगी। सो, उनके जरिए जाट वोटों का बंटवारा हो ऐसा भाजपा की सदिच्छा हो सकती है लेकिन यह इच्छा पूरी होगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता है।

मुश्किल में एमएमसीजी क्षेत्र

हिंदुस्तान लीवर से लेकर आईटीसी, मेरिको, बजाज कंज्यूमर केयर और ज्योति लैब्स तक को अगले सितंबर तक बिक्री बढ़ने की संभावना नजर नहीं आ रही है। इस वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के नतीजों ने इन कंपनियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।

आम उपभोग के सामान बनाने वाली (एफएमसीजी) लगभग सभी कंपनियां इस निष्कर्ष पर हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बदहाली के कारण फिलहाल उनके कारोबार की संभावनाएं मद्धम हैं। हिंदुस्तान लीवर से लेकर आईटीसी, मेरिको, बजाज कंज्यूमर केयर और ज्योति लैब्स तक को अगले सितंबर तक बिक्री बढ़ने की संभावना नजर नहीं आ रही है। इस वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (सितंबर-दिसंबर) के नतीजों ने इन कंपनियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। तेल, साबुन, सैंपू, टूथपेस्ट आदि जैसी रोजमर्रा की उपभोग वस्तुएं बनाने वाली इन कंपनियों का आधे से ज्यादा बाजार ग्रामीण इलाकों में है।

इसलिए जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था चमकती है, तो इन कंपनियों का कारोबार भी चमकता है। वैसे शहरों में भी औसत आबादी की आमदनी का स्तर वैसा नहीं है, जो ग्रामीण बिक्री में गिरावट की भरपाई कर सके। तो इन कंपनियों की मुसीबत में जिस बात पर बार-बार रोशनी पड़ती है, वह ग्रामीण उपभोग का स्तर है। एमएमसीजी कंपनियों का आकलन है कि महंगाई, फसल बिक्री संबंधी समस्याओं और असामान्य मौसम ने वास्तविक ग्रामीण आमदनी में सेंध लगा रखी है।

हालात गंभीर बनाने में काफी हाथ सरकारी नीतियों का है। हम प्याज के बाजार के ताजा हाल पर गौर करें, तो इस परिस्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। प्याज के दाम बढ़ने के कारण सरकार ने 31 मार्च तक उसके निर्यात पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद बाजार में फिर से प्याज की कीमतें 33 प्रतिशत बढ़ने की खबर आई है। इसे देखते हुए (अखबारी रिपोर्टों के मुताबिक) सरकार निर्यात पर रोक कम-से-कम तीन महीने और बढ़ाने जा रही है। इस तरह महंगाई के समय विश्व बाजार से ऊंची कीमत मिलने का जो फायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलता, उससे उसे वंचित कर दिया गया है। ऐसा अक्सर अलग-अलग फसलों के साथ होता रहता है। सरकार की चिंता शहरी उपभोक्ताओं को लेकर रहती है। उसकी कीमत कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़े लोग चुकाते हैं। इन दोनों हितों में कैसे तालमेल बने, इस दिशा में उचित प्रयास सरकार की तरफ से नहीं किए गए हैं। नतीजतन, गांवों में मंदी है और उसका साया एफएमसीजी कारोबार पर भी पड़ रहा है।

उनको ही नागरिकता दीजिए, जो योग्य हों

ठाकुर दास भार्गव
वरिष्ठ राजनेता

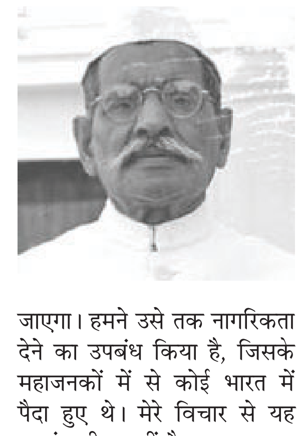

नागरिकता की समस्या सदा बड़ी कठिन समस्या रही है। नागरिकता की धारणा का विकास कई शताब्दियों में हुआ है। पहले केवल वही किसी देश केनागरिक माने जाते थे, जो वहां जन्मे हों, परंतु आजकल पंजीयन द्वारा, नए क्षेत्र के देश में भी नागरिक बन जाते हैं।

जहां तक नागरिकता प्राप्त करने का संबंध है, भारतीय विधि में जन्म को प्रमुख स्थान दिया गया है, किंतु मेरी समझ से केवल जन्म नागरिकता का अधिकार देने के लिए पर्याप्त नहीं है। मान लीजिए कि कोई विदेशी पति-पत्नी कुछ समय के लिए भारत में आते हैं और यहीं पत्नी बच्चे को जन्म देती है, तो क्या वह बच्चा भारत का नागरिक समझा जाएगा? नागरिक तो उसे समझा जाना चाहिए, जिसके माता-पिता भारतीय हों या वह भारत में पलकर यहीं संपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार हों, किंतु इस विषय में अब कुछ कहना व्यर्थ होगा, क्योंकि ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम के अंतर्गत और हमारे संविधान के अंतर्गत भी हमने यह बात मान ली है कि यदि इंग्लैंड में पंजीबद्ध किसी जहाज में भारत में किसी का जन्म हो, तो भी वह इंग्लैंड में पैदा हुआ समझा जाएगा। हमने उसे तक नागरिकता देने का उपबंध किया है, जिसके महाजनकों में से कोई भारत में पैदा हुए थे। मेरे विचार से यह उपबंध ठीक नहीं है।

देशीयकरण के मामले में भी आप देखेंगे कि उसमें मूल निवास के संबंध में कोई शर्त नहीं है, परंतु पांच वर्ष से यदि वह रहता है, तो काफी होगा। यह शर्त भी कि वह भविष्य में भी भारत में रहेगा, किंतु अब पक्का राष्ट्रजन कच्चा राष्ट्रजन और प्रथम अथवा द्वितीय कोटि के राष्ट्रजन आदि का अंतर मेरी समझ में नहीं आता।

यह भी कहा गया था कि सारे शरणार्थियों को आवेदन पत्र देना चाहिए और शपथ पत्र लगाना चाहिए। ...मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि क्या तीस लाख बंगालियों के लिए शपथपत्र देना संभव होगा और क्या वे इतना पैसा व्यय कर सकेंगे? ...सरदार पटेल ने कहा था कि इन लोगों के लिए पूर्वी बंगाल खाली करवाना चाहिए। पंडित नेहरू ने अन्य उपायों का उल्लेख किया था। वहां के 30-40 लाख हिंदू अभी भी शरणार्थी बने हुए हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि पूर्वी बंगाल से हिंदुओं का आना कैसे बंद होगा? वे हमारे ही शरीर के अंग हैं।मैं 1948 और उसके बाद आने वालों में कोई अंतर नहीं समझता। मैं जानता हूं कि हमारी सरकार इस विषय में विवश है और हमें यह भी मानना पड़ेगा कि हमारी नीति असफल रही है। पाकिस्तान की नीति हमें हानि पहुंचाने की रही है। उसने विभाजन के समय और बाद में भी अनेक वादे किए, पर जब भी मौका पाया, धक्का ही दिया और वहां से हिंदुओं को निकाल दिया। दूसरी बात यह है कि पंजीकृत लोगों को उनकी राष्ट्रीयता से कभी वंचित नहीं किया जा सकता, जबकि देशीयकरण किए गए लोगों की स्थिति भिन्न है, परंतु हम इस प्रस्थापित विधेयक में क्या उपबंध कर रहे हैं? हम यह उपबंध रख रहे हैं कि जो शरणार्थी सरकार से विद्वेष करे अथवा जिसे किसी अपराध में एक वर्ष की सजा मिली हो, उसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। अतः कोई व्यक्ति सरकार के प्रति वफादार नहीं है, इसलिए उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाए, यह कुछ उचित नहीं जान पड़ता...।

मैं पाकिस्तान के मुसलमानों का बहुत बड़ी संख्या में असम जाकर वहां की राज्य सरकार के लिए संकट उत्पन्न करना भी सहन नहीं कर सकता। ...आज कश्मीर, असम और पूर्वी बंगाल में क्या हो रहा है, यह हम सभी जानते हैं। मैं तथ्यों से भला कैसे मुख मोड़ लूं? क्या आज जिस प्रकार यहां मुसलमान रहते हैं, उसी प्रकार इस देश के लोग पाकिस्तान में रह सकते हैं? ...जहां तक पाकिस्तानी राष्ट्र जनों का संबंध है, नागरिकता के हक पर कुछ प्रतिबंध रहने चाहिए, जिससे कि हमारे देश की सुरक्षा को खतरा न उत्पन्न हो सके। ...सरकार को चाहिए कि पूर्वी बंगाल से आने वाले लोगों के पंजीयन पर रोक लगाए। ...उन्हीं व्यक्तियों को यहां का नागरिक बनाए, जो इसके वास्तव में योग्य हों। मैंसंयुक्त समिति से निवेदन करूंगा कि वह भी इस पर ध्यान दे...।

पाकिस्तान से मैं घबराता नहीं हूं। पाकिस्तान के लोगों से मुझे प्रेम है, क्योंकि हमारी संस्कृति एक जैसी है। विभाजन के पूर्व हम लोग एक ही देश के निवासी थे, परंतु मैं चाहता हूं कि हम अपनी विधियां इस प्रकार की बना लें कि हमारे देश की सुरक्षा में कमजोरी न आए।

(लोकसभा में दिए गए उद्बोधन से)

पूरी सहानुभूति से हम देंगे लोगों को आश्रय

गोविंद बल्लभ पंत
तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री

नागरिकता विधेयक को एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्देशित करने से संबंधित इस प्रस्ताव पर गत तीन दिनों से चर्चा हो रही है। इस पर बोलने वाले सभी वक्ताओं ने इसके महत्व का अनुभव किया है। मैं सभा को बधाई देता हूं कि यहां इतने आला दर्जे का वाद-विवाद होता रहा है। ...हम चाहते हैं कि विभिन्न राष्ट्रों में बंधुत्व और बढ़े। हम कांग्रेस में चिरकाल से ही विश्व संघ और विश्व नागरिकता का स्वप्न देखा करते थे। राष्ट्रमंडल की नागरिकता हमारे ऊपर बिना कोई बोझ लादे, हमें उस लक्ष्य के निकट ले जाती है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें इससे कुछ हानि पहुंचेगी। हमें इससे पहले ही बहुत लाभ प्राप्त होते रहे हैं। माननीय सदस्यगण कृपया यह याद रखें कि हमारे हजारों राष्ट्रजन इंगलिस्तान में व्यवसाय, उद्योग, वाणिज्य और सरकारी नौकरी या अन्य पेशों में लगे हुए हैं। उपनिवेशों में और ग्रेट ब्रिटेन से निकट संबद्ध देशों में लगभग 50 लाख भारतीय हैं।...

अब कुछ माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि विस्थापितों को पंजीबद्ध किए बिना ही हम उनका नागरिकता का अधिकार मान लें। वास्तव में नागरिकता का अधिकार तो है ही, पर पंजीयन न होने से भ्रामक स्थिति पैदा हो जाएगी। ...पंजीयन के बाद ही उनको नागरिकता के विशेषाधिकार मिलेंगे, अतः पंजीयन आवश्यक है । मैं नहीं समझता कि विस्थापित व्यक्तियों को कोई बहुत बड़ी असुविधा होगी, क्योंकि वे पुनर्वास चाहेंगे और सहायता मांगेंगे। अतः उनमें से प्रत्येक को उसके लिए पंजीबद्ध होना पड़ेगा।

जहां तक नागरिकता के अधिकार से वंचित करने का प्रश्न है, विस्थापित व्यक्तियों के संबंध में विशेष विचार किया जाना उचित है। आशा है, प्रश्न के इस पहलू पर संयुक्त समिति द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। ...यह नागरिकता किसी व्यक्ति को अधिकार के कारण नहीं प्राप्त होती है। यह

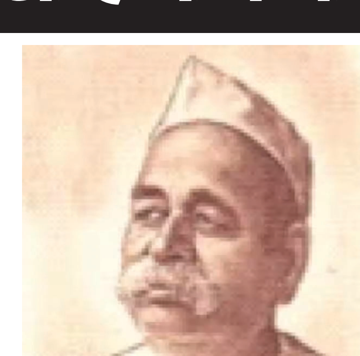

एक प्रकार का विशेषाधिकार है, जो उसे दिया गया है। अतः यदि वह ऐसा आचरण अपनाता है, जो प्रशासन के प्रभारी व्यक्तियों के मार्ग का रोड़ा बनता है, तो वह विशेषाधिकार खो देता है, जो उसे प्रत्यक्षतः इस शर्त पर दिया गया था कि वह केवल एक या दो बार ही नहीं, अपितु निरंतर रूप से उचित आचरण करेगा। जब वह उस ढंग का आचरण करता है, तो उस अधिकार को खो देता है। अन्य देशों में भी ऐसा उपबंध है। ...इस समय हम संसार में शांति के लिए कार्य कर रहे हैं। हमने अपने व्यवहार से संसार की समस्याओं के प्रति अपना और अपने देश के लिए सम्मान का स्थान बना लिया है। वर्तमान परिस्थितियों में इन मूल समस्याओं के संबंध में यह हमारे आचरण के अनुकूल होगा, यदि हम इस देश में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता का अधिकार प्राप्त करने की अनुमति दें, परंतु यह केवल एक पवित्रता की भावना ही नहीं है, जो मुझे ऐसा भाव व्यक्त करने का प्रोत्साहन देती है। अन्य देशों में हमारे नागरिकों की संख्या, यहां उनके देशों के नागरिकों की संख्या की अपेक्षा अधिक है। संसार भर में हमारे लगभग 50 लाख लोग फैले हुए हैं। हमारी अभिरुचि यह है कि इस संबंध में समस्त देशों से उदार संबंध हों। अतः यदि हम कुछ व्यक्तियों को आश्रय देते हैं,तो हम इससे अन्य देशों में अपने लाखों लोगों के लिए समान व्यवहार का नैतिक आधार बनाते हैं। अतः इस बारे में अपनी स्वार्थमय दृष्टि से भी ऐसा उपबंध बनाना हमारे हित में है...।

एक यह भी सुझाव दिया गया था कि यदि कोई व्यक्ति ध्वजा का अपमान करता है, उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाए। मैं आशा करता हूं कि कोई व्यक्ति इतना मूर्ख न होगा कि वह इतना पतनकारी कार्य करे। हम अपने नागरिकों की सद्भावनाओं पर विश्वास कर सकते हैं। ...मैंने मुख्य बातों का उल्लेख करने का प्रयत्न किया है। छोटी-छोटी बातों का उल्लेख करना मैं आवश्यक नहीं समझता। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य महसूस करेंगे कि यह विधेयक अच्छा बनाया गया है और इससे उस उद्देश्य की पूर्ति होगी, जो इसे बनाने वालों ने सोच रखा है। आजकल हम जो भी कर रहे हैं, उसका बड़ा महत्व है। पराधीनता तो कुछ समय पहले ही समाप्त हो गई थी, परंतु अब भी हम और हमारे समाज को नागरिकता के पूर्ण रूप में विकसित होना है। इस विधेयक से हम यही प्राप्त करना चाहते हैं। मैं आशा करता हूं कि प्रवर समिति इस विधेयक के प्रत्येक खंड पर ध्यानपूर्वक विचार करेगी ।

(लोकसभा में दिए गए उद्बोधन से)

स्टेशन रोड, इंदिरा मार्केट, दुर्ग के प्रतिष्ठित संस्थान
विज्ञापन के लिए संपर्क करे:-
9827806026,
7869620239

Sargam Musicals
Deals in All Kinds of Musical Instrument Sales & Repair
DURG:- Near Tarun Adlabs Station Road, Durg (C.G.) Durg, Ph. 2330588, 9826660688
RAIPUR:- Near Manju Mamta Reaustaurant, M.G. Road Raipur. Ph. 4013288, 9303876196

गंजेपन से मुक्ति मात्र 1 घंटे में
COMPLETE FAMILY SALON
हेयर रिप्लेसमेंट, 100% संतुष्टि की गारंटी
पहले बाद में
JITU'Z CUT N SHINE
93009-11331
रंगोली बेंगल्स के सामने, जयसवाल इलेक्ट्रानिक के बाजू में इंदिरा मार्केट, स्टेशन रोड, दुर्ग (छ.ग.)

प्रिंट और डीजिटल मीडिया में
सभी प्रकार के विज्ञापन
के लिए
संपर्क करें
Mob.-:
9303289950
7987166110

श्रीकंचनपथ
छत्तीसगढ़

इनकम TAX
ITR फाईल
बनवायें मात्र 500/- में
TDS, GST, TAX Expert
सम्पर्क- शेखर गुप्ता
9300755544
onlytds@gmail.com WWW.ONLYTDS.COM

समाज और मानवता के लाभ के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करें - राज्यपाल हरिचंदन

22 मेधावी विद्यार्थियों को दिया गया स्वर्ण पदक

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन एमिटी विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने विद्यार्थियों से समाज व समग्र मानवता के लाभ के लिए अपने ज्ञान का पूर्ण उपयोग करने हेतु संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समाज के गरीब व वंचित लोगों के लिए विद्यार्थियो को काम करना है।

पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित दीक्षांत समारोह में राज्यपाल श्री हरिचंदन ने 22 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक, 16 को रजत पदक और 5 को कांस्य पदक प्रदान किए। समारोह में वर्ष 2023 बैच के 681 विद्याार्थियों को स्नातक एवं स्नातकोत्तर की उपाधियां वितरित की गईं। विश्वविद्यालय द्वारा डीएआरई के सचिव और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग नई दिल्ली के महानिदेशक डॉ. हिमांशु पाठक को मानद

डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई । कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव ने की।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि दीक्षांत समारोह का यह दिन विद्यार्थियों के जीवन का महत्वपूर्ण चरण है। सभी ने अपने विषयों में ज्ञान प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि डिग्रियों से अधिक, जो ज्ञान और मूल्य यहां हासिल किया है वह पूरे जीवन में उनका मार्गदर्शन करेगा। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरा है। आज दुनिया की नजरों में भारत के प्रति धारणा उल्लेखनीय रूप से बदल गई है, कई देशों के साथ आपसी सहयोग के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण सामने आया है। इस देश के युवा के रूप में हमारी अर्थव्यवस्था के विकास और राष्ट्र के समग्र विकास के अग्रदूत बनने जा रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि जीवन के हर विषय में मूल्य-आधारित शिक्षा, रचनात्मकता, नवाचार, अनुसंधान और विकास के माध्यम से ही हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और गरीबी, बीमारियों, बेरोजगारी, भूख और पर्यावरणीय चुनौतियों सहित कई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।

राज्यपाल ने कहा कि यह गर्व विषय है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में जगह बनाने के लिए लगातार प्रयास किए। शैक्षणिक पाठ्यक्रम गतिशील होना चाहिए, यह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के बराबर होना चाहिए और उद्योग-केंद्रित और अनुसंधान उन्मुख होना चाहिए। सरकार ने वित्तपोषण और उद्यमिता तथा नौकरी सृजन को बढ़ावा देने के लिए 'स्टार्ट-अप इंडिया' अभियान शुरू किया है। राज्यपाल ने विद्यार्थियो से उद्यमी बनने का आग्रह किया।

उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने अपने संबोधन में विद्यार्थियो से आग्रह किया कि वे एक लक्ष्य निर्धारित कर उसे प्राप्त करने तक सीमित न रहे बल्कि अपने लिए खुला आसमान रखें और ऊंची उड़ान भरे । कड़ी मेहनत और लगन से अपने सपनों को पूरा करें। समारोह को छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष प्रो. कर्नल उमेश कुमार मिश्रा भी ने भी संबोधित किया। कुलाधिपति डॉ. डब्ल्यू सेल्वामूर्ति ने विश्वविद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । इस अवसर पर विश्विद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. अशोक के चौहान, अध्यक्ष डॉ. असीम के चौहान, कुलपति डॉ. पियूष कांत पाण्डे, फैकल्टी मेंम्बर्स, डीन, प्राध्यापक, छात्र-छात्राएं एवं उनके परिजन भी उपस्थित थे।

खास खबर

आदर्श आचार संहिता लागू होते ही निर्वाचन संबंधी समितियां शुरू करेंगी अपना काम - डॉ गौरव सिंह

रायपुर। लोकसभा निर्वाचन के लिए आचार संहिता लागू होते ही विभिन्न निगरानी समितियों सक्रिय होंगी। मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति, आदर्श आचार संहिता समिति तथा निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण समिति निर्वाचन संबंधी विभिन्न पहलुओं पर बारिकी से नजर रखेंगी और सावधानियां बरतेंगी। कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने आज कलेक्टर सभाकक्ष में लोकसभा निर्वाचन के तैयारियों की समीक्षा बैठक में यह बात कही। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ गौरव सिंह ने कहा कि जैसे ही राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग चुनाव के तारीखों की घोषणा करेगा, वैसे ही आदर्श आचार संहिता लागू होना मानी जाएगी। सभी अधिकारी इसका पालन कराना सुनिश्चित करें। सभी अधिकारी निष्पक्ष होकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। कलेक्टर ने कहा कि आचार संहिता लगते ही संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत 24 घण्टे के भीतर शासकीय कार्यालयों से और 48 घण्टों के भीतर सार्वजनिक स्थानों से प्रचार-प्रसार की सामग्री हटा दी जाएगी। नगरीय निकायों में और जनपद पंचायतों में टीम बनाकर यह कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। विरूपण की कार्रवाई गंभीरतापूर्वक हो। इसमे किसी भी प्रकार की कोताही ना बरतें। नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा, एडीएम देवेन्द्र पटेल, कीर्तीमान राठौर सहित सभी जोन कमिश्नर उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ के दो आईपीएस अफसरों का केंद्र में इंस्पेक्टर जनरल के पद पर मनोनयन

रायपुर। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ कैडर के 2 आईपीएस सहित 47 आईपीएस अफ्सरों को आईजी इम्पैनल किया है। 2005 बैच के अमरेश मिश्रा और राहुल भगत केंद्र में इंस्पेक्टर जनरल इम्पैनल हो गये हैं। बता दें कि दोनों आईपीएस अफ्सरों अभी छत्तीसगढ़ में अहम ओहदा संभाल रहे हैं। जानकारी के अनुसार आदेश आज जारी कर दिया गया है। जिसके अनुसार रायपुर के आइपीएस अमरेश मिश्रा को आईजी पद पर इमपैनलमेंट किया गया है, वे रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक हैं। इसके साथ ही उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अंवेषण ब्यूरो और एंटी करप्शन ब्यूरो का पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है। इसी तरह आइपीएस राहुल भगत को भी आईजी पद पर इमपैनलमेंट किया गया है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राहुल भगत सीएम सचिवालय के सचिव हैं तथा नए विभाग सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

कार्यकर्ता पद के लिए मंगाये गये दावा-आपत्ति आवेदन

रायगढ़। एकीकृत बाल विकास परियोजना रायगढ़ (शहरी)अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र पूछापारा वार्ड क्रमांक 11, आंगनबाड़ी केन्द्र गौशाला पारा वार्ड क्रमांक 14, आंगनबाड़ी केन्द्र झोपड़ीपारा वार्ड क्रमांक 35 एवं आंगनबाड़ी केन्द्र राजीवगांधी नगर ए वार्ड क्रमांक 36 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पद के लिए जारी प्राविधिक/अनंतिम मूल्यांकन पत्रक पर दावा-आपत्ति आवेदन मंगाये गये है। आवेदिका 18 मार्च से 2 अप्रैल 2024 सायं 5.30 बजे तक सीधे परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना, रायगढ़ (शहरी) में दावा-आपत्ति आवेदन जमा कर सकते है।

अंतिम व्यक्ति तक मिले योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ - मंत्री देवांगन

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। वाणिज्य एवं उद्योग और श्रम मंत्री एवं मुंगेली जिले के प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय काम-काज की समीक्षा की। बैठक में मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन हो और उसका लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मिलना चाहिए।

उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने दायित्वों का गंभीरतापूर्वक निर्वहन करते हुए जनहित के कार्य करने प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि गांव, गरीब और आम किसानों को योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ मिले, जिससे बेहतर

विकास होगा और जिले का नाम रोशन होगा। प्रभारी मंत्री देवागंन ने विभागीय योजनाओं एवं गतिविधियों की समीक्षा बैठक के दौरान पात्र हितग्राहियों को अच्छी गुणवत्ता का चावल उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने महिला एवं बाल विकास में भर्ती के संबंध में प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लिया और संबंधित अधिकारी को नियमानुसार निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों को फसल बीमा योजना का शत-प्रतिशत लाभ सुनिश्चित करने तथा जल जीवन मिशन के कार्य को मिशन मोड में पूरा करने के लिए कहा। बैठक में मुंगेली विधायक श्री पुन्नूलाल मोहले ने ट्रांसफार्मर की उचित व्यवस्था करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए, ताकि जिले में कम वोल्टेज की समस्या ना हो, उन्होंने स्वीकृत निर्माण कार्यों को भी तत्काल शुरू करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी बढ़िया कार्य कर रहे हैं, आगे भी इसी तरह कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। कलेक्टर राहुल देव ने प्रभारी मंत्री श्री देवांगन को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ आमजनों तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा बेहतर कार्ययोजना बनाकर लगातार प्रयास किया जा रहा है।

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना, पीएम उज्जवला योजना, जल जीवन मिशन, पीएम विश्वकर्मा योजना, स्वच्छ भारत मिशन आदि महत्वाकांक्षी योजनाओं सहित स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, रोजगार, वन आदि विभागीय योजनाओं एवं गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा हुई और लक्ष्य के अनुरूप आवश्यक प्रगति लाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर वनमंडलाधिकारी सत्यदेव शर्मा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तर के अधिकारी उपस्थित थे।

साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान मूल्यांकन परीक्षा 17 को

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायगढ़। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान नई दिल्ली की पहल पर 17 मार्च, 2024 दिन-रविवार को प्रात: 10 बजे से सायं 5 बजे तक राष्ट्रव्यापी बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान मुल्यांकन परीक्षा आयोजन किया जा रहा है। जिसमें ऐसे शिक्षार्थी जिनका पूर्व में पढना-लिखना अभियान अंतर्गत प्रमाणिकरण नहीं हुआ है, जो मोहल्ला साक्षरता केन्द्रों में पूर्व में पढ़ाई किये हैं, वे इस मूल्यांकन परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। शिक्षार्थी सुविधानुसार उक्त समय के भीतर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। शिक्षार्थी को प्रश्न पत्र हल करने के लिए 3 घण्टे का समय दिया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा निति-2020 में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को प्रमुख रूप से फोकस किया गया है। जिले को शत-प्रतिशत साक्षर करने के उद्देश्य से केन्द्र प्रवर्तीत योजना उल्लास नव भारत साक्षरता का क्रियान्वयन जिला साक्षरता मिशन प्राधिकारण के अध्यक्ष एवं कलेक्टर के कुशल मार्ग दर्शन में प्रारंभ किया गया है।

शिक्षा मंत्री को मिले प्राइमरी स्कूल की बालिकाओं के मासूमियत से भरे पत्र

बच्चों ने लिखा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान से बालिकाओं के लिए है बहुत उम्मीद

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। प्रदेश भर के प्राइमरी स्कूल की छोटी-छोटी बालिकाओं के लिखे पत्र आज स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के पास पहुंचे। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ अभियान के अंतर्गत इन सुंदर पत्रों को आज शिक्षा मंत्री ने देखा। हर पत्र अपने में मासूमियम से भरा बेटियों की अथाह प्रतिभा की दास्तां कह रहा था। इन पत्रों में छोटे बच्चों ने अपनी तुतलाहट भरी भाषा में चित्रों के माध्यम से एक बालिका भ्रुण की दास्तां कही।

एक बच्ची ने एक चित्र बनाया, इसमें एक बीज है जिसके भीतर भ्रुण है जिसकी हत्या की जा रही है। यह नहीं होता तो वो वृक्ष की असीम संभावना को छूता, उसी तरह बालिका भी अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण करती।

मंत्री अग्रवाल इन पत्रों को पढ़कर और इनके मार्मिक चित्रों को देखकर भावुक हुए। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों ने मुझे पत्र के माध्यम से सुंदर संदेश भेजे हैं उन्हें मेरी ओर से धन्यवाद प्रेषित करना है। मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि इन छोटी बालिकाओं के शब्दों का संसार सीमित है लेकिन इनकी संवेदना का संसार बहुत विस्तृत है। जिस तरह से इन्होंने एक बालिका भ्रुण की हत्या की भयावह दास्तां अपने चित्रों से व्यक्त की है वो इनकी गहरी भावनाओं को बताता है। इन प्रतिभाशाली बालिकाओं से छत्तीसगढ़ का भविष्य उज्ज्वल लगता है।

शिक्षा मंत्री अग्रवाल ने कहा कि लड़कियों के जीवन में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षा से लड़कियां आत्मनिर्भर बनकर समाज में अपना योगदान देती हैं। शिक्षा लड़कियों को सशक्त बनाती है और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने में मदद करती है। लड़कियों की शिक्षा समाज के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब लड़कियां शिक्षित होती हैं, तो वे अपने परिवार और समाज के लिए बेहतर निर्णय ले सकती हैं। वे अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकती हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। हमारी सरकार हमेशा से ही महिला सशक्तिकरण के पक्षधर रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में महिला आरक्षण बिल लाए हैं।

इसी क्रम में राज्य में महिलाओं के सम्मान के लिए मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन के अंतर्गत महिलाओं के खाते में महतारी वंदन योजना की राशि भी पहुंचने लगी है।

शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए पुलिस की भूमिका अहम - नीलेश क्षीरसागर

पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा उप पुलिस अधीक्षकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नीलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने कहा है कि राज्य की सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की है, साथ ही आदर्श आचार संहिता का पालन कराने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने के लिए विभिन्न निगरानी दलों के साथ भी पुलिस बल का समन्वय जरूरी है।

उन्होंने विधान सभा निर्वाचन 2023 के शांतिपूर्ण संपन्न होने पर पुलिस बल की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि निर्वाचन व्यय पर निगरानी रखने के लिए

पुलिस का राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय करना आवश्यक है। श्री क्षीरसागर ने कहा कि संवेदनशील मतदान केन्द्रों में शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस बल अन्य एजेंसियों की मदद से विशेष योजना तैयार कर कार्य करें। श्री क्षीरसागर न्यू सर्किट हाउस सभागार में लोकसभा निर्वाचन पूर्व पुलिस अधिकारियों के एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उदघाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले के निर्देशानुसार आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण में प्रदेश के 22 जिलों के पुलिस अधीक्षक, 11 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं 65 उप पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। इस अवसर पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पी एस ध्रुव सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

प्रशिक्षण के दौरान लोकसभा निर्वाचन के लिए राज्य पुलिस नोडल अधिकारी ओ पी पाल ने कहा है कि प्रदेश में शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों की भूमिका अहम है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा निर्वाचन के दौरान राज्य पुलिस तथा जिला प्रशासन इस बात का ध्यान रखे कि बाहर से आने वाले अर्ध सैनिक बलों की टुकड़ियों को आवश्यक जरूरतों के लिए कोई असुविधा ना हो।

एक दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान राष्ट्र स्तरीय मास्टर ट्रेनर श्री यू एस अग्रवाल ने आदर्श आचरण संहिता, मीडिया मॉनिटरिंग एवं कंट्रोल सेंटर एवं शिकायत सेल के संबंध में जानकारी दी। वहीं मास्टर ट्रेनर अपूर्व प्रियेश टोप्पो ने निर्वाचन व्यय निगरानी , विनय अग्रवाल ने पोस्टल बैलेट, इलेक्ट्रानिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम (ईटीपीबीएस) और इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिक्रेट (ईडीसी) पर प्रकाश डाला। प्रशिक्षण के दौरान सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था एवं निर्वाचन संबंधी विभिन्न विषयों पर भी विशेषज्ञों ने जानकारियाँ साझा की।

Since 1972
CROWN® - TV
Choice Of Millions
LED Available 16 -20 -22 - 24 - 32-40-50-55-65

Premier sales
8959493000
A Leela Electronics
9425507772
Reena Electronics
9329132299
Shree Electronics
7000827361
CONTACT
Maa Durga Electronics
9827183839
Rohit Electronics
94242-02866
Authorised Distributers For Chhattisgarh
Trade Enquiry: 98262-52372

खास खबर...

राजनांदगांव निगम में अधोसंरचना विकास और मूलभूत कार्यों के लिए 8.54 करोड़ रुपए स्वीकृत

रायपुर। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा राजनांदगांव नगर निगम में अधोसंरचना विकास के विभिन्न कार्यों और अत्यावश्यक मूलभूत कार्यों के सुचारू संचालन के लिए कुल आठ करोड़ 54 लाख 19 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। विभाग द्वारा राजनांदगांव नगर निगम के विभिन्न वार्डों में अधोसंरचना विकास के 42 कार्यों के लिए सात करोड़ 54 लाख 19 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं। शहर में अत्यावश्यक मूलभूत कार्यों के सुचारू संचालन के लिए चुंगी क्षतिपूर्ति मद के अंतर्गत अनटाइड फंड के रुप में विभाग द्वारा एक करोड़ रुपए की भी स्वीकृति दी गई है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग द्वारा इन राशियों की स्वीकृति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्रीसाव ने सभी कार्यों को अच्छी गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राजनांदगांव में पत्रकारों के लिए आबंटित आवासीय भूखंड में द्वितीय चरण के शेष आवश्यक विकास कार्यों के लिए अधोसंरचना मद के अंतर्गत करीब दो करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इनमें प्रेस क्लब कॉलोनी में 97 लाख 19 हजार रुपए लागत के पी.सी.सी. रोड निर्माण, 34 लाख 64 हजार रुपए लागत के आर.सी.सी. नाली निर्माण और 68 लाख आठ हजार रुपए लागत के बाउंड्रीवॉल निर्माण कार्य शामिल हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा राजनांदगांव नगर निगम के लिए अधोसंरचना मद से स्वीकृत कुल सात करोड़ 54 लाख 19 हजार रुपए की राशि से शहर के विभिन्न वार्डों में सी.सी. रोड, पी.सी.सी. रोड, नाला एवं नाली निर्माण, सामुदायिक भवनों के निर्माण, उद्यान निर्माण, शौचालय निर्माण, गेट, दुकान एवं शेड निर्माण, डोम निर्माण, इंटरलॉकिंग, बाउंड्रीवॉल तथा अहाता निर्माण के कार्य कराए जाएंगे।

उपभोक्ता अधिकार दिवस का पर किया गया संगोष्ठी का आयोजन

रायपुर। आज डी.पी. शर्मा अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम रायपुर की गरिमामय उपस्थिति में उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए श्री शर्मा के द्वारा आम उपभोक्ताओं के अधिकार के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई तथा उपस्थित समस्त जागरूक उपभोक्ताओं को अपने परिवेश में आने वाले सभी उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा किसी भी किस्म की ठगी होने पर उचित मंच में शिकायत करने की प्रक्रिया की जानकारी दिया। साथ ही मुख्य सचिव द्वारा वर्तमान परिवेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले ठगी प्रकरणों के प्रति बचाव के निर्देश का पालन करने की जानकारी दी गई।
इस अवसर पर खाद्य नियंत्रक विधिक माप विज्ञान के निरीक्षक गण, उपभोक्ता प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में विधि छात्रगण उपस्थित रहे।

डब्ल्यूडीसी एवं पीएमकेएसवाई 2.0 योजनांतर्गत संविदा पद भर्ती के दावा आपत्ति की सूचना

रायपुर। डब्ल्यू.डी.सी एवं पी एम.के.एस.वाई. 2.0 योजनांतर्गत जिला रायपुर विकासखंड तिल्दा में संचालित परियोजना में डब्ल्यू.सी.डी.सी हेतु तकनीकी विशेषज्ञ (अभियांत्रिकी), लेखापाल सह डाटा एण्ट्री आपरेटर डब्ल्यू.सी.डी एवं परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी हेतु डब्ल्यू.डी.टी संदस्य (यांत्रिकी), डब्ल्यू.डी.टी संदस्य (समूह विकास) डब्ल्यूडीटी संदस्य (आजीविका), लेखापाल सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर डब्ल्यू.डी.टी के संविदा अनारक्षित पद भर्ती हेतु विज्ञापन जारी कर आवेदन पत्र मंगाया गया था। चयन समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का स्क्रुटनी कर मेरिट सूची तैयार की गई है। मेरिट सूची को दावा आपत्ति हेतु रायपुर जिले के ऑफिसियल वेबसाईड तंपचनतण्हवअण्पद में 15 मार्च को अपलोड कराया गया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने लिये पांच अहम फैसले

सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ा चार फीसदी, पेंशनरों को भी होगा लाभ

- सातवें वेतनमान के एरियर्स के अंतिम किश्त की राशि भी मिलेगी
- कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित की गई समिति
- पंचायत सचिवों को 55 दिनों की हड़ताल का होगा वेतन भुगतान, अर्जित अवकाश में समायोजित होगी हड़ताल अवधि
- पत्रकारों के खिलाफकिये गये कथित झूठे मुकदमों एवं उत्पीड़न के मामलों में न्याय दिलाने गृह सचिव की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अधिकारी-कर्मचारियों तथा मीडियाबंधुओं के हित में पांच अहम फैसले लिये। इनमें अधिकारी-कर्मचारियों को सातवें वेतनमान पर चार प्रतिशत का महंगाई भत्ता देना भी शामिल है। इसका लाभ पेंशनरों को भी मिलेगा। महंगाई भत्ते की यह राशि एक मार्च 2024 की तिथि से मिलेगी। राज्य के अधिकारी-कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त की राशि का भुगतान भी होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती निहारिका बारिक की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई है जो कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में समीक्षा करेगी और इनके निराकरण से संबंधी सुझाव शासन को प्रस्तुत करेगी। ग्राम पंचायत सचिवों को भी राहत देते हुए उनके 55 दिनों की हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। अर्जित अवकाश में यह हड़ताल अवधि समायोजित होगी। इन निर्णयों से होली के त्यौहार में कर्मचारियों के परिवारों में खुशियों के और भी रंग भर जाएंगे।

अब महंगाई भत्ता हुआ 46 प्रतिशत

महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में 04 प्रतिशत महंगाई भत्ते में एवं पेंशनरों के महंगाई राहत में 04 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। यह महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत 1 मार्च 2024 से दिया जाएगा। इसके फ्लस्वरूप महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर सातवें वेतनमान में 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत तथा छठवें वेतनमान में यह 230 प्रतिशत हो जाएगी। इस निर्णय से राज्य के 3 लाख 90 हजार कर्मचारी तथा 1 लाख 20 हजार पेंशनर लाभान्वित होंगे। इस निर्णय से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को प्रतिमाह 68 करोड़ रुपए तथा साल में 816 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त होगा।

सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त भी मिलेगी

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों-कर्मचारियों की सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त प्रदान करने की घोषणा भी की।

हड़ताल अवधि का वेतन पंचायत सचिवों को मिलेगा

मुख्यमंत्री ने आज संवेदनशील निर्णय लेते हुए ग्राम पंचायत सचिवों को भी राहत दी। ग्राम पंचायत सचिव पिछले साल 16 मार्च 2023 से 9 मई 2023 तक कुल 55 दिन हड़ताल पर थे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्राम पंचायत सचिवों की हड़ताल अवधि को उनके अर्जित अवकाश में समायोजित करते हुए उन्हें 55 दिनों का वेतन भुगतान किया जाएगा। इस निर्णय से राज्य शासन पर 70 करोड़ रुपए का व्यय-भार आएगा।

कर्मचारियों की समस्याओं पर बनी समिति

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी भाईयों ने बहुत सी मांगों और समस्याओं के संबंध में अपनी बातें हमसे साझा की हैं। हम उनकी समस्याओं का पूरी संवेदनशीलता से समाधान करेंगे। उन्होंने बताया कि इन समस्याओं के हल के लिए प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती निहारिका बारीक की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति बनाई है। समिति विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर शासन को कर्मचारी हित में उचित सुझाव देगी। अध्यक्ष के अलावा प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, सचिव वित्त सदस्य होंगे और सचिव सामान्य प्रशासन विभाग (शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा) सदस्य सचिव होंगे।

पत्रकारों को न्याय दिलाने गृह सचिव की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी

मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकारों एवं मीडियाजगत से जुड़े बंधुओं के खिलाफ उत्पीड़न की अनेक शिकायतें सामने आईं थीं। इस संबंध में हम गृह सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की घोषणा करते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि इस कमेटी में पत्रकारों समेत अन्य सदस्यों को भी नियुक्त किया जाएगा।

कलेक्टर ने विद्यार्थियों से लिया फीड बैक

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह आज मोतीबाग परिसर स्थित तक्षशिला पुस्तकालय का निरीक्षण करने पहुँचे। उन्होंने लाइब्रेरी में अध्ययनरत युवाओं से लाइब्रेरी में जुड़े सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं पर चर्चा किया।

कलेक्टर ने सभी युवाओं को बारी बारी सुना एवं उनके सुझाओं पर अमल करने की बात कही। सभी युवाओं ने एक स्वर में माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह का तक्षशिला लाइब्रेरी प्रारंभ करने पर उनका धन्यवाद किया। कलेक्टर ने कहा कि यहाँ पर रीडिंग ज़ोन के साथ ही पुस्तकालय का भी सुविधा है। आप सभी के भविष्य एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की किताब उपलब्ध कराई गई। अभी भी यदि कोई किताब अगर उपलब्ध नहीं है तो आप अपना सुझाव पूर्ण विवरण के साथ दीजिए हम उस पर यथासंभव आवश्यक कार्यवाही करेंगे। निरीक्षण के दौरान अध्ययनरत युवाओं ने कलेक्टर से कुछ किताबों की माँग की थी जिसको रोजगार अधिकारी एवम नोडल अधिकारी श्री केदार पटेल द्वारा कलेक्टर के निर्देश पर कुछ समय के अंतराल पर ही लॉ सहित अन्य किताबों को उपलब्ध करा दिया गया। उन्होंने कहा कि इस लाइब्रेरी की कुछ सुविधा नई है और जब कोई नई सुविधा प्रारंभ होती है तब उसको मूर्त रूप में आने के लिए समय लगता है। शासन-प्रशासन की कोशिश और आप सभी युवाओं के सुझाव से तक्षशिला लाइब्रेरी को हमेशा बेहतर से भी बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। डॉ सिंह ने कहा कि परिसर में साफ-सफाई रखी जाए और गर्मी को देखते हुए पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करें। साथ ही परिसर में संचालित कैंटिन में उपयुक्त दरों पर नाश्ता और बैठने की व्यवस्था भी की जाए। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा, रोजगार अधिकारी एवं लाइब्रेरी के नोडल अधिकारी केदार पटेल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

सड़कों पर महीनों भटक रहे रुपेश देवांगन भी अब अपने पैरों से अपने घर जा सकेगा

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने जन चौपाल के दौरान रुपेश देवांगन को उनका आधार कार्ड सौपा। श्री देवांगन जो एक वर्ष पूर्व रायपुर के सड़कों पर बदहवांस हालात में भटक रहे थे, जिनको रायपुर के अपना घर आश्रम के वालंटियर्स द्वारा आश्रम लाया गया जहा उनका बेहतर सेवा और देख भाल किया जा रहा है। देवांगन जिनका दोनो पैर नहीं है, उनको कृत्रिम पैर लगवाने की पहल चल रही है जिसके लिये श्री देवांगन का आधार कार्ड की आवश्यकता थी। देवांगन के आधार कार्ड के बारे में जानकारी लेने कलेक्टर जन चौपाल ले जाया गया, जहां कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह से मिलकर रुपेश देवांगन के बारे में जानकारी देते हुए मदद के लिए निवेदन किया गया। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश से श्री रुपेश का आज आधार निकलवाया गया एवं कलेक्टर के द्वारा श्री रुपेश को आधार कार्ड सौंपा गया। अब रूपेश देवांगन का आधार प्राप्त होने से उनका मूल निवास के बारे में जानकारी प्राप्त हो सका है। अपना घर आश्रम और ज़िला प्रशासन रुपेश देवांगन के परिवार से संपर्क साधने का प्रयास कर रही है।

छत्तीसगढ़ सरकार के तीन माह पूरे

सरकार ने लिए जनहित में बड़े फैसले, लोगों ने जताया आभार

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से यहां उनके निवास कार्यालय में विधायक रोहित साहू के नेतृत्व में राजिम विधानसभा के क्षेत्रवासियों ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा तीन माह की अल्प अवधि में जनहित में लिए गए बड़े फैसलों के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया।

लोगों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कम समय में ही सभी वर्गों के हित को ध्यान में रखते हुए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। जिसका लाभ पूरे प्रदेश के लोगों को मिल रहा है।

प्रतिनिधिमंडल ने चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय से कहा कि नई सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में राज्य में 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों को स्वीकृति देकर विकास का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी की गारंटी के अनुरूप राज्य के 12 लाख से अधिक किसानों को धान का 2 वर्ष का बकाया बोनस 3716 करोड रुपए भी तत्काल प्रदान किया गया। साथ ही प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी की घोषणा भी अमल में लाई गई। राज्य में इस वर्ष 145 लाख टन धान की रिकॉर्ड खरीदी की गई है। किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल के मान से भुगतान भी किया गया है। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 24 लाख 72 हजार किसानों के खाते में 13,320 करोड रुपए की राशि अंतरित की गई है।

प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ सरकार के तीन माह के कार्यों पर हर्ष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री से कहा कि राज्य की माता बहनों के लिए सरकार ने महतारी वंदन योजना लागू कर दी है। जिसके तहत 70 लाख से अधिक माताओं के खाते में ?1000 के मान से 655 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई है। युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है।

पीएससी की पिछली परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया गया है।अयोध्या में भगवान श्रीराम का दर्शन करने के लिए श्रीरामलला दर्शन योजना शुरू हुई है। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास के लिए नियद नेल्लानार यानी आपका अच्छा गांव योजना प्रारंभ हुई है। इस तरह छत्तीसगढ़ सुशासन और विकास के पथ पर बहुत तेजी से अग्रसर है। इस अवसर पर सर्वश्री प्यारेलाल सोनकर, राजेश साहू मनीष हरित, राजू साहू, मोती निषाद, रामाधार साहू, केजउ निषाद, अंकुर पहाड़िया, ईश्वर साहू तथा भागीरथी सिन्हा आदि उपस्थित थे

नंदनी रोड, लिंक रोड, सर्कुलर मार्केट, जवाहर मार्केट पावर हाउस, भिलाई के प्रतिष्ठित संस्थान विज्ञापन के लिए संपर्क करेंः-
9303289950, 9827806026, 8962815243

प्रीति ड्रेसेस
मेन्स एण्ड लेडिस वियर
जवाहर मार्केट, पावरहाउस, भिलाई
मो. 9589230033, 9993840094

● जीन्स
● टी-शर्ट
● शर्ट
● ट्राउजर
भारत जींस
जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई

आरना इंटरप्राईजेस
कांटावाला
वाटर प्यूरी फायर के विक्रेता एवं सुधारक
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त
इलेक्ट्रानिक तराजू एवं सीसीटीवी कैमरा के विक्रेता व सुधारक
सर्कुलर मार्केट केम्प-2, भिलाई, न्यू जेपी स्पोर्ट्स के सामने
7828844440, 9993045122
नया बस स्टैण्ड, शिव मंदिर रोड, दुर्ग, 09981370285, 9302833333

आर्टिफिशियल ज्वेलरी के विक्रेता
अनुप ट्रेंडर्स
सर्कुलर मार्केट, केम्प-2, पावर हाउस, भिलाई

प्रमोद इंटरप्राइजेस
गेंहू, चांवल एवं दाल के थोक विक्रेता
लिंक रोड, केम्प-2, भिलाई-दुर्ग
फोनः 0788-2225449, 93290-13017

Hotel Shiv Prabha Inn. & Town King
The Family Restaurant
46-C Market, Near Sapana Talkies & Hotel Apana Keshari Lodge, Power House, Bhilai, Distt.-Durg (C.G.)
9893215251, 8966981590
Email.: ranjanaguptakeshari@gmail.com

BIHAR BOOT HOUSE
Jawahar Market, Power House
Bhilai 9826181183

गुलदस्ते में लगे फूलों को लंबे समय तक रखना चाहते हैं तरोताजा तो अपनाएं ये टिप्स

रंग-बिरंगे और खुशबूदार फूलों के जरिए घर की सजावट करना एक बेहद कारगर और मशहूर तरीका है। फूल अपनी सुंदरता के कारण हर जगह की खूबसूरती में चार-चांद लगा देते हैं। बगीचों और गमलों में लगाने के अलावा लोग अपने कमरों में भी फूल लगाना पसंद करते हैं। इन्हें आकर्षक गुलदस्तों में रखकर सजवाट की जाती है। अगर आप भी गुलदस्ते के फूलों को लंबे समय तक ताजा बनाए रखना चाहते हैं तो ये टिप्स अपनाएं।

सही प्रकार का गुलदस्ता चुनें

फूलों को लंबे समय तक खिला हुआ रखने के लिए हमेशा सही गुलदस्ता चुनना चाहिए। किसी भी अवशेष या बचे हुए डिटर्जेंट आदि से मुक्त एक साफ फूलदान लें और उसमें ही फूलों को रखें। हल्के और बेहद नाजुक फूलों को लंबे गुलदस्ते में रखना चाहिए, वहीं भारी फूलों के डंठल को छोटा काटकर उन्हें एक छोटे और चौड़े फूलदान में रखें। इससे उन्हें फैलने के लिए अतिरिक्त जगह मिलेगी।

पानी में रखने से पहले फूलों के तनों को 2 इंच काट लें

अपने फूलों को गुलदस्ते में रखने से पहले इनके तनों को 2 इंच तक काट लें। बगीचे की कैंची आपको सबसे साफ कट देगी, लेकिन नियमित कैंची भी उपयोग की जा सकती है। अधिक जल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए तनों को 45 डिग्री एंगल पर काटें। गुलाब जैसे फूलों के तनों में हवा के बुलबुले फंस जाते हैं, जिससे पानी का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। इस समस्या को रोकने के लिए तनों को पानी में रखकर काटें।

पानी का सही तापमान सुनिश्चित करें

ज्यादातर फूल कमरे के तापमान वाले पानी में सबसे अच्छी तरह खिले हुए रहते हैं। ऐसे फूल, जिनमें भूमिगत संरचनाएं होती हैं, वे ठंडे पानी में रखने चाहिए। चाहे आप ठंडे या गुनगुने पानी का उपयोग कर रहे हों, अपने फूलदान को तीन-चौथाई स्तर तक ही भरें। इसमें समय-समय पर पानी डालते रहें क्योंकि फूल पानी को सोखते रहते हैं। बसंत के मौसम में ये सुंदर फूल आसानी से उगाए जा सकते हैं।

कठोर वातावरण से फूलों को रखें दूर

अपने ताजे फूलों को सीधी धूप में, गर्म उपकरणों के पास, पंखे, एयर कंडीशनिंग या खुली खिड़कियों से आने वाली हवा के झोंकों के पास रखने से बचें। ट्यूलिप जैसे कुछ फूल विशेष रूप से गर्मी के प्रति संवेदनशील होते हैं। आपको कटे हुए फूलों को ताजे फलों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि इनसे एथिलीन गैस के अंश निकलते हैं, जो मुरझाने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं।

अपने फूलों के लिए घर पर बनाएं खाना

फूलों को ताजा रखने के लिए उन्हें एक तरह का खाना दें। आप अपने घर पर ही यह फॉर्मूला बना सकते हैं। अपने फूलदान में 3 भाग पानी, 1 भाग स्प्राइट और बैक्टीरिया को मारने के लिए ब्लीच की कुछ बूंदें डालें। फूलों के भोजन के लिए एक और आम नुस्खा कारगर होता है। इसमें पानी के 1/4 भाग में 2 बड़े चम्मच ऐपल साइडर सिरका, 2 बड़े चम्मच चीनी और 1/2 चम्मच ब्लीच मिलकर उसमें फूल लगाएं।

आर्टिकल 370 ने दुनियाभर में पार किया 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा

यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के दौरान आई चुनौतियों को दिखाया गया है। यह फिल्म पिछले तीन सप्ताह से बॉक्स ऑफिस और दर्शकों के दिलों पर राज कर रही हैं। 20 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन किया है। अब आर्टिकल 370 ने नया कीर्तिमान हासिल किया है। दरअसल, फिल्म ने दुनियाभर में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू लिया है।

जियो स्टूडियो ने इस खबर की जानकारी देते हुए अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक वीडियो साझा किया है। उन्होंने लिखा, ऐतिहासिक फैसले के पीछे की कहानी देखकर देश गर्व से चमक रहा है। निर्माताओं ने नया पोस्टर साझा करते हुए अपनी खुशी जाहिर की और लिखा, लोगों की शक्ति। एक वादे की ताकत। प्रेम की ताकत। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई की बात करें बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, आर्टिकल 370 ने रिलीज के 21वें दिन 80 लाख रुपये का कारोबार किया, जिसके बाद इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 69 करोड़ रुपये हो गया है। बॉक्स ऑफिस पर आर्टिकल 370 का सामना किरण राव की फिल्म लापता लेडीज से हो रहा है। अजय देवगन की फिल्म शैतान भी दर्शकों का मनोरंजन कर रही है।

विभाजन पर बनी बंगाल 1947 से बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी देवोलीना भट्टाचार्जी

देवोलीना भट्टाचार्जी का नाम छोटे पर्दे की उन अभिनेत्रियों में शामिल है, जिन्होंने अपनी उम्दा अकादारी के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई है। देवोलीना ने अपने करियर की शुरुआत टीवी शो सवारे सबके सपने... प्रीतो से की थी, लेकिन उन्हें पहचान साथ निभाना साथिया से मिली।लाल इश्क और छोटी सरदारनी के अलावा देवोलीना कुछेक वेब सीरीज में भी नजर आ चुकी हैं। अब देवोलीना बॉलीवुड में डेब्यू करने को तैयार हैं। उनकी पहली फिल्म बंगाल 1947 है।

भारत के विभाजन की पीड़ा को बयां करती फिल्म बंगाल 1947 का फर्स्ट लुक सामने आ गया है। फिल्म 1947 में हुए विभाजन के दौरान खासकर बंगाल पर पड़े उसके प्रभाव को दर्शाती है। गदर फिल्म के सह-निर्देशक अकाश्यदीप लामा द्वारा निर्देशित बंगाल 1947 का निर्माण कॉन्फेड प्रोडक्शन्स के बैनर तले हुआ है। इस प्रोडक्शन कंपनी का नेतृत्व दो बार के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक सतीश पांडे कर रहे हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत धारावाहिक हम लोग के लिए छायाकार के रूप में की थी। उनके साथ ऋषभ पांडे और अकाश्यदीप लामा भी निर्माता के तौर पर जुड़े हैं।

यह फिल्म पीरियड ड्रामा और रोमांस के मिश्रण का वादा करती है। साथ ही यह एक अनोखी प्रेम कहानी पर प्रकाश डालती है, जिसे लेखक-निर्देशक आकाशादित्य लामा ने स्क्रीन पर उतारा है।

मोशन पोस्टर में लिखा है, फिल्म बंगाल 1947 का फर्स्ट लुक जारी, यह 29 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह फिल्म 1947 में भारत के विभाजन की पड़ताल करती है।

फिल्म में देवोलीना भट्टाचार्जी, सोहिला कपूर, ओमकार दास मानिकपुरी, आदित्य लखिया और अंकुर अर्मन मुख्य भूमिकाओं में हैं। प्लेटून डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा फिल्म 29 मार्च 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी।

जैकलीन फर्नांडीज ने ऑरेंज बॉडीफिट ड्रेस में ढाया कहर

सोशल मीडिया का तापमान हुआ हाई

बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज ने अपने इंस्टाग्राम पर हाल ही में कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो अपने लुक से इंटरनेट का तापमान बढ़ा रही हैं। इन तस्वीरों में जैकलीन को ऑरेंज कलर के बॉडीफिट रिवीलिंग ड्रेस देखा जा सकता है। खुले बालों और लाइट मेकअप के साथ उनका ये अंदाज़ फैंस को बेहद पसंद आ रहा है। तस्वीरों में जैकलीन अलग-अलग पोज दे रही हैं और उनकी हर अदा दिलकश लग रही है। जैकलीन के इस पोस्ट को कुछ ही घंटों में लाखों लाइक्स मिल चुके हैं और फैंस कमेंट्स की भरमार कर रहे हैं। एक फैन ने लिखा, आप हमेशा इतनी खूबसूरत कैसे लगती हैं जैकलीन वहीं दूसरे ने कमेंट किया, ऑरेंज आपका रंग है।

जैकलिन फर्नांडीस श्रीलंकाई मूल की, भारतीय अभिनेत्री व मॉडल है जो हिन्दी फिल्मों में कार्यरत है। वे 2006 की मिस श्रीलंका यूनिवर्स रह चुकी है। उन्हें 2010 का सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री का आईफा और स्टारडस्ट पुरस्कार फिल्म अलादीन के लिए प्रदान किया गया था।

फिल्म मैं अटल हूं ने ओटीटी प्लेटफॉर्म जी-5 पर दी दस्तक

पंकज त्रिपाठी की फिल्म मैं अटल हूं को 19 जनवरी, 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। बेशक इस फिल्म में उन्होंने एक बार फिर अपनी उम्दा अदाकारी का लोहा मनवाया है, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। अब मैं अटल हूं ओटीटी प्लेटफॉर्म जी-5 पर दस्तक दे चुकी है। ऐसे में जो दर्शक इस फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं देख पाए, वह अब इसे ओटीटी पर देख सकते हैं।

फिल्म मैं अटल हूं में पंकज त्रिपाठी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का किरदार निभाया है। इस फिल्म में अटल बिहारी वाजपेयी की कवि से राजनेता बनने तक की जर्नी को बखूबी से दिखाया गया है। पंकज त्रिपाठी के अलावा इस मूवी में पीयूष मिश्रा, राजा सेवक, दया शंकर पांडे और एकता कौल समेत कई अन्य कलाकार भी नजर आए थे।

रिलीज हुआ पटना शुक्ला का ट्रेलर

अब वकील बनकर इंसाफ दिलाएंगी रवीना टंडन

रवीना टंडन एक बार फिर ओटीटी पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। उनकी नई फिल्म पटना शुक्ला का ट्रेलर जारी किया गया है, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पर दस्तक देगी। फिल्म में रवीना एक वकील तन्वी शुक्ला की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म का ट्रेलर शनादार है।

ट्रेलर में एक ऐसे वकील की कहानी दिखाई गई है, जो अभी तक खुद को साबित नहीं कर पाई है। ट्रेलर में देखने को मिलता है कि तन्वी किचन में अपने पति और उनके दोस्तों के लिए पकौड़े तल रही है। तभी उनका पति अपने दोस्तों के साथ तन्वी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि छोटे मोटे केस इसे मिल जाते हैं, लेकिन मेरी पत्नी एफिडेबिट अच्छा बनाती है। तन्वी को अपने पति की ये बात चुभ जाती है। फिर तन्वी के पास एक लड़की अपना केस लेकर आती है, जो रोल नंबर स्कैम से जुड़ा होता है।

तन्वी इस केस को लड़ने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन ये केस तन्वी के लिए कई सारी मुसीबतें खड़ी कर देता है। मीडिया पर ये केस बहुत हाइलाइट हो जाता है। तन्वी को धमकियां मिलनी शुरू हो जाती है। उसके पति की नौकरी भी चली जाती है। लेकिन तन्वी हार नहीं मानती है और डटी रहती है। इस केस को जीतने में अपनी पूरा जी-जान लगा देती है।

रवीना के अलावा इस फिल्म में अनुष्का कौशिक, जतिन गोस्वामी, चंदन रॉय सान्याल और मानव विज भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे। वहीं दिवंगत एक्टर सतीश कौशिक भी इस मूवी में नजर आ रहे हैं। बता दें कि ये फिल्म 29 मार्च को हॉटस्टार पर रिलीज होगी।

सलमान खान ने भी इस फिल्म का ट्रेलर मजेदार अंदाज में शेयर किया है। उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि कभी लिंकिंग रोड, कभी कैडल रोड, कभी पेडर रोड, कभी ऑर्थर रोड... ढूंढता तुम्हें हर जगह... हमें बीना बताए रवीना कुछ नया लेकर आई है। वहीं सलमान के इस पोस्ट पर रवीना ने कमेंट करते हुए लिखा कि ना कार्टर रोड ना टनर रोड।। अब मिलूंगी सीधा पटना। बन गई हूं तन्वी शुक्ला। मेरा स्वागत नहीं करोगे।

घर के लिए ढूंढ रहे हैं रूम फ्रेशनर तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान

आखिर कौन नहीं चाहता होगा कि वो घर आए, तो उसे एक आराम और सुकूनदायक माहौल मिले, जिससे उसका मूड बेहतर हो। इसके लिए हम कई तरह के रूम फ्रेशनर्स का इस्तेमाल करते हैं। यही नहीं मेहमानों के आने से पहले भी हम घर को चमकाने के साथ-साथ उसे खुशबूदार बनाने के लिए महंगे-महंगे रूम फ्रेशनर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वे लोग यह नहीं जानते कि हर घर का अपना एक अलग माहौल होता है और उसके हिसाब से ही उन्हें रूम फ्रेशनर्स चुनने चाहिए, जो उनके घर से मेल खाता हो। अगर आपको भी नहीं पता कि अपने कमरे या घर के लिए एक सही रूम फ्रेशनर्स का चुनाव कैसे करें, तो आइये जानते हैं।

घर के लिए सही रूम फ्रेशनर्स कैसे चुनें

अपनी जरूरतों को पहचानें:- सही रूम फ्रेशनर का चुनाव करने के लिए सबसे पहले आपको इस बात को समझना होगा कि आप किस तरह के फ्रेग्रेंस को पसंद करते हैं। आपको फ्लोरल खुशबू चाहिए या सीट्रिक, वुडी या फिर मसालेदार। इसके बाद अपने पसंद के फ्रेशनर को चुनें। इसे समझने से आप अपने लिए सही खुशबू को ढूंढ सकते हैं।

जगह को समझें:- हर कमरे की एक अलग आभा और वाइब होती है और उसके मुताबिक ही आपको अलग-अलग रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, बाथरूम के लिए हल्की, ताजा सुगंध का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि आरामदायक वॉर्म फ्रेग्रेंस लिविंग रूम के लिए आदर्श हो सकती है। रूम फ्रेशनर का चयन करने से पहले उस स्थान के आकार और कार्य पर विचार करें जो उसके साथ अच्छा काम करेगा।

एलर्जी और सेंसिटिवटी का ध्यान रखें:- रूम फ्रेशनर चुनते समय अपनी एलर्जी और सेंसिटिवटी को ध्यान में जरूर रखें। ऐसी सुगंधों से बचें जो एलर्जी का कारण बन सकती हैं या सांस संबंधी समस्याएं बढ़ा सकती हैं। अगर आप या आपके घर में कोई सांस संबंधी परेशानी से जूझ रहा हो, तो हाइपोएलर्जेनिक और फ्रेग्रेंट फ्री प्रोडक्ट चुनें।

नेचुरल कम्पाउंड की तलाश करें:- ऐसे रूम फ्रेशनर चुनें जिनमें नेचुरल कम्पाउंड्स शामिल हों। ऐसे फ्रेग्रेंट न केवल पर्यावरण को लाभ पहुंचाते हैं, बल्कि आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंट की तुलना में इनमें अधिक अरोमा और सुखद खुशबू होती है। ऐसे प्रोडक्ट्स की तलाश करें जिनमें एसेंशियल ऑयल और प्लांट-बेस्ड एक्स्ट्रैक्ट्स मौजूद हों।

मौसम के मुताबिक चुनें:- मौसम के मुताबिक अपने रूम फ्रेशनर को बदलते रहना चाहिए। गर्मी, बारिश और सर्दी के मौसम के हिसाब से फ्रेशनर चुनना काफी फायदेमंद हो सकता है। जैसे गर्मियों के लिए फ्लोरल, वैसे ही दालचीनी या वेनिला जैसी गर्म, मसालेदार सुगंध सर्दियों के लिए सबसे अच्छी होती है।

तृप्ति डिमरी ने बढ़ाई अपनी फीस

भूल भुलैया 3 के लिए डबल किया है चार्ज!

संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल की सक्सेस के बाद से तृप्ति डिमरी नेशनल क्रश बन गई हैं। फिल्म में एक्ट्रेस का रोल कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था फिर भी उन्होंने अपनी एक्टिंग से फैंस को दीवाना बना लिया है। एनिमल की सक्सेस के बाद से तृप्ति मेकर्स की पहली पसंद बन गई हैं। उन्हें कई प्रोजेक्ट्स ऑफर हो रहे हैं। तृप्ति की भूल भुलैया 3 में भी एंट्री हो चुकी है। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म के लिए एक्ट्रेस ने अपनी फीस बढ़ा दी है। तृप्ति ने अपनी फीस डबल कर दी है। फिर भी मेकर्स उन्हें खुशी-खुशी बढ़ी हुई फीस देने के लिए तैयार हैं।

रिपोर्ट्स की माने तो एनिमल की सक्सेस के बाद इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स पहले की तुलना में तीगुने हो गए थे। फॉलोअर्स में इतना बदलाव आने के बाद ही उन्होंने अपनी फीस बढ़ाने का फैसला लिया है। भूल भुलैया 3 के मेकर्स से तृप्ति ने अपनी फीस बढ़ाने के लिए कहा है और वो मान भी गए हैं क्योंकि वो फीस प्रोडक्शन के बजट में फिट बैठती है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक तृप्ति ने एनिमल में अपने रोल के लिए 40 लाख फीस चार्ज की थी। अब उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ गई है तो उन्होंने ये फीस बढ़ाकर 80 लाख कर दी है। हालांकि फीस बढ़ाने के बाद भी तृप्ति की फीस कार्तिक आर्यन से बहुत कम है। वो कार्तिक की फीस का सिर्फ 20 प्रतिशत चार्ज कर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्तिक आर्यन फिल्म के लिए 45-50 करोड़ चार्ज कर रहे हैं।

कुछ समय पहले खबरें आ रही थीं कि तृप्ति को कई साउथ इंडियन फिल्में ऑफर हो रही हैं और उन्होंने प्रभास के साथ फिल्म साइन की है। इन अफवाहों पर तृप्ति ने रिएक्ट किया था। उन्होंने कहा- मैंने अभी तक कोई फिल्म साइन नहीं की है। हालांकि अगर वहां से ऑफर आएंगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी।

दुर्ग, सुपेला और कोहका प्रतिष्ठित संस्थान विज्ञापन के लिए संपर्क करें:-
9303289950, 9827806026, 8962815243

BANK P.O. & CLERK, MBA, RLY., SSC.
Paul Sir
रामा कोचिंग
135, NEW CIVIC CENTER, Bhilai Ph. 0788-6560005

चौरसिया ज्वेलर्स
आकर्षक सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता
बेन्टेक्स एवं ग्रहरत्न उपलब्ध यहां
उचित ब्याज दर पर गिरवी रखी जाती है
मुक्तिधाम रोड, रामनगर, सुपेला, भिलाई
9827938211, 9827171332

पीएम ई-बस सेवा योजना- छत्तीसगढ़ के चार शहरों को मिली 240 सिटी बसों की स्वीकृति

रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को मंजूरी

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। शहरों में सार्वजनिक परिवहन के ढांचे को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम ई–बस सेवा योजना प्रारंभ की गई है। योजना के तहत राज्यों को शहरों की जनसंख्या के आधार पर बसों की संख्या निर्धारित की गई है। जिसके अनुसार रायपुर को 100, दुर्ग–भिलाई को 50, बिलासपुर को 50 तथा कोरबा को 40, इस प्रकार कुल 240 ई–बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के चार प्रमुख शहरों रायपुर, दुर्ग–भिलाई, बिलासपुर और कोरबा को पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की मंजूरी दी है। यह घोषणा न केवल छत्तीसगढ़ के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है, बल्कि पूरे देश के लिए एक मील का पत्थर भी है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ और हरित भारत के सपने को साकार करने में एक महत्वपूर्ण कदम है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस मौके पर कहा कि राज्य में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत से शहरी परिवहन में क्रांति आएगी। यह पहल हमें पर्यावरणीय संरक्षण के साथ-साथ नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक कदम आगे ले जाती है। उन्होंने नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को इस चैलेंज में सफल होने पर बधाई दी एवं भविष्य में और शहरों को भी इस योजना में शामिल करने के लिए प्रयास करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के कारण हम नवाचार और स्थिरता की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। यह योजना हमारे नागरिकों के लिए एक उपहार है, जो न केवल पर्यावरण को बचाएगी, बल्कि हमारे जीवन को भी सुगम बनाएगी। ई–बसों का आगमन छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए एक नई और स्वच्छ परिवहन सेवा का द्वार खोलेगी। इन बसों के शुरू होने से पर्यावरणीय प्रदूषण में कमी आएगी और शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार होगा। साथ ही ऊर्जा की बचत भी होगी।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की यह योजना राज्यों को मिलने वाली केंद्रीय मदद को पारदर्शिता और उनके प्रदर्शन से जोड़ने की केंद्र की कोशिश का हिस्सा है। केंद्र सरकार की मंशा है कि यह योजना शहरों में मेट्रो के विकल्प या उसके सहयोगी साधन के रूप में विकसित हो ताकि लोगों को किफायती, भरोसेमंद और सुगम परिवहन की सुविधा मिले।

देश के समस्त राज्यों से राष्ट्रीय चैलेंज अंतर्गत प्राप्त शहरों के प्रतिस्पर्धात्मक के विश्लेषण उपरांत भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की केंद्रीय स्वीकृति तथा संचालन कमेटी (ष्टस्स्ष्ट) की छठवीं बैठक 01 मार्च को रायपुर तथा सातवीं बैठक 14 मार्च में छत्तीसगढ़ के 3 शहरों के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

अपनी तरह की इस पहली योजना में केंद्र सरकार द्वारा शहरों को बसों की खरीद तथा उनके संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिसमें एक बड़ा हिस्सा शहरों में बस डिपो जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भी खर्च किया जाएगा। योजना की सामान्य शर्तों में यह भी शामिल है कि प्रोजेक्ट के तहत दिए जाने वाले पैसे का थर्ड पार्टी ऑडिट अनिवार्य होगा, ताकि पूरी पारदर्शिता रहे। शहरों को हर तीन महीने में बसों के संचालन का हिसाब–किताब देना होगा। योजना के तहत तीन तरह की बसें स्टैंडर्ड, मीडियम और मिनी चलाई जाएंगी। शहरों को जनसंख्या के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है। बीस से चालीस लाख तक की आबादी वाले शहरों को 150, दस से बीस लाख तथा पांच से दस लाख तक की आबादी वाले शहरों को 100–100 तथा पांच लाख से कम आबादी वाले शहरों को 50 ई–बसों की पात्रता थी जिसके आधार पर रायपुर को 100 मीडियम ई–बस, दुर्ग–भिलाई को 50 मीडियम ई–बस, बिलासपुर को 35 मीडियम तथा 15 मिनी ई–बस और कोरबा को 20 मीडियम तथा 20 मिनी ई–बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार बसों का क्रय तथा संचालन एजेंसी का चयन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा और केंद्रीय सहायता सुनिश्चित किलोमीटर संचालन के लिहाज से दी जाएगी और अगर बसें इससे कम किलोमीटर चलती हैं तो केंद्रीय सहायता उसी के अनुपात में कम हो जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा शहरों के प्रदर्शन के आधार पर पैसा दिया जाएगा। ई–बस सेवा से छत्तीसगढ़ के शहरों में कम कार्बन उत्सर्जन से वायु गुणवत्ता में सुधार तथा पर्यावरणीय संरक्षण के साथ–साथ कम ऊर्जा खपत और बेहतर ईंधन दक्षता एवं आरामदायक सुखद यात्रा अनुभव प्राप्त होगा।

खास खबर

स्वास्थ्य विभाग के बर्खास्त 05 हजार कर्मी हुये बहाल और 25 हजार कर्मियों को मिला रूका वेतन

रायपुर। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी–कर्मचारी 21 अगस्त 2023 से 12 सितम्बर 2023 तक हड़ताल में थे। इस अवधि का अवकाश व रूका वेतन स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर जारी कर दिया गया है। इसका लाभ प्रदेश के लगभग 30 हजार स्वास्थ्य कर्मियों को मिला हैं। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन ने स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल को आभार व्यक्त किया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन के आंदोलन कर रहे कर्मचारियों का उस दौरान कार्यालय में अनुपस्थित रहने के कारण बर्खास्तगी व वेतन अस्वीकृत कर दिया गया था। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की थी। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने मुलाकात के बाद स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों को इन विसंगतियों को दूर करने के निर्देश दिये थे। निर्देश के परिपालन में बर्खास्त पांच हजार कर्मचारियों को वापस सेवा में ले लिया गया है। साथ ही 25 हजार कर्मचारियों का अंदोलन के दौरान रूका वेतन भी स्वीकृत कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन ने स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल का निज निवास कार्यालय में गत दिवस सौजन्य भेंट कर धन्यवाद दिया है। आंदोलन के दौरान चिकित्सा शिक्षा विभाग के दो हजार कर्मचारियों के रूके हुये वेतन को देने का आदेश जारी नहीं किया गया हैं। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने इन कर्मियों का भी वेतन जारी करने का निवेदन स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल से किया हैं।

जिले के हाट-बाजारों और प्रमुख बसाहटों में एलईडी वैन एवं कला जत्था दल कर रहे योजनाओं का प्रचार-प्रसार

जगदलपुर। राज्य शासन के जनसम्पर्क विभाग द्वारा एलईडी वैन तथा कला जत्था दलों के माध्यम से शासन की जनहितकारी योजनाओं का प्रचार–प्रसार हाट–बाजारों और प्रमुख बसाहटों में किया जा रहा है। इस दिशा में एलईडी वैन के माध्यम से योजनाओं पर केंद्रित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया जा रहा है,साथ ही कला जत्था दल द्वारा गीत,नाटक–प्रहसन के जरिए योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। जिसे ग्रामीणजन उत्सुकता के साथ देखकर लाभान्वित हो रहे हैं। जनसम्पर्क विभाग द्वारा एलईडी वैन एवं कला जत्था दल के माध्यम से विगत दिवस धरमपुरा कॉलेज परिसर में आयोजित किसान सम्मेलन में योजनाओं से सम्बंधित लघु फिल्म प्रदर्शन किया गया। वहीं कला जत्था दल द्वारा योजनाओं पर केंद्रित प्रेरक प्रस्तुति दी गई। इसके साथ ही जगदलपुर विकासखण्ड के पुसपाल,बस्तर ब्लॉक के भैंसगांव एवं सुलेंगा,तोकापाल ब्लॉक के कुरेंगा एवं कलेपाल,दरभा विकासखंड के छिंदबहार,चिंगपाल साप्ताहिक बाजार सहित बकावंड विकासखण्ड के राजनगर एवं जुनवानी में एलईडी वैन एवं कला जत्था दल के माध्यम से महतारी वंदन योजना,कृषक उन्नति योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना,प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इत्यादि का प्रचार–प्रसार किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को जनमन पत्रिका सहित विभिन्न जनहितकारी योजनाओं पर आधारित प्रचार साहित्य वितरित किया गया।

खाद्य मंत्री बघेल ने 1 करोड़ 78 लाख के विकास कार्यों का किया भूमिपूजन

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल ने बेमेतरा जिले के नवागढ़ विकासखंड के नगर पंचायत मारो में भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने 1 करोड़ 78 लाख 14 हजार रूपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया । विकास कार्यों के भूमि पूजन में विभिन्न वार्डो में आर सी सी नाली, सी सी रोड, एवं मंगल भवन शामिल है। खाद्य मंत्री ने हितग्राहियों नये राशन कार्ड का भी वितरण किया।

खाद्य मंत्री बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत 24.72 लाख किसानों के खाते में 13,320 करोड़ रूपए की अदान सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में दी गई है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का नया रिकार्ड प्रदेश में बना है। 24 लाख 72 हजार से अधिक किसानों से 145 लाख मीट्रिक टन की धान खरीदी की गई है। धान खरीदी के एवज में किसानों को 31 हजार 914 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अन्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी परिवारों को आगामी 5 वर्ष तक नि:शुल्क खाद्यान वितरण शुरू हो गया है। राज्य के 67 लाख 92 हजार 153 राशनकार्डधारी परिवार लाभान्वित हो रहे है। प्रदेश की महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत 36 लाख 76 हजार गैस कनेक्शन का लाभ मिला है। इस अवसर पर टार्जन साहू, अंजू बघेल, परस वर्मा, धनलाल देशलहरे, मती आराध्या माधो छत्रिय, एवं समस्त अधिकारी–कर्मचारी उपस्थित थे।

तिल्दा नेवरा में 5.24 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास

विकास कार्यों से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे: मंत्री बृजमोहन अग्रवाल

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल आज तिल्दा–नेवरा में आयोजित लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने यहां 5.24 करोड़ रूपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। श्री अग्रवाल ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ससाहोली का नाम जैन मुनि श्री विद्या सागर जी महाराज के नाम पर रखने की घोषणा की साथ ही तिल्दा नेवरा में बीएड कॉलेज खोले जाने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही स्वामी आत्मानंद प्रियदर्शिनी स्कूल और शासकीय विद्यालय भीमोरी में निर्माण कार्य के लिए 25–25 लाख रुपए देने की घोषणा की।

मंत्री श्री अग्रवाल ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आने के बाद विकास के कार्यों में तेजी आई है। डबल इंजन सरकार की वजह से बेहतर समन्वयन के कारण योजनाओं को क्रियान्वित करने में आसानी हो रही है।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और विकास कार्यों से रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। श्री अग्रवाल ने यहां 157 लाख रुपए से निर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में 50 सीटर बालक छात्रावास, 247 लाख रुपए की लागत से बने 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र, 42 लाख रुपए से निर्मित उप पंजीयक कार्यालय भवन और 27 लाख से बने आयुष्मान आरोग्य मंदिर हमर क्लिनिक का लोकार्पण किया। साथ ही बी.एन.बी. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूल सासाहोली और स्वामी आत्मानंद कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 18–18 लाख रुपए की लागत से बनने वाले प्रार्थना शेड का शिलान्यास किया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने की और सांसद सुनील सोनी विशिष्ठ अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर लेमिक्षा गुरू डहरिया, अनिल अग्रवाल, ईश्वर यदु, देवादास टंडन, विभागीय अधिकारी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित थे।

पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास हेतु अगले 25 वर्षों के रोडमेप पर हुई चर्चा

पर्यावरण को सुरक्षित रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी : ओपी चौधरी

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास की परिकल्पना को सार्थक करने के लिये 'छत्तीसगढ़ विजन 2047' पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत ने की।

पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास हेतु अगले 25 वर्षों के रोडमेप पर चर्चा करते हुए आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओपी चौधरी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी को बदलते हुए वक्त को समझना चाहिए और आने वाली पीढ़ी के लिए खुद को भी बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार सतत विकास के लिए अपने बजट में 2047 में छत्तीसगढ़ को भी विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में देखना चाहती है और इसके लिए लॉन्ग टर्म गोल के रूप में ही अमृतकाल विजन डॉक्यूमेंट ञ्च 2047 की तैयारी की जा रही है जिसे छत्तीसगढ़ की स्थापना के दिन 1 नवंबर को लांच किया जाएगा।

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास का होना अनिवार्य है और इस सेक्टर में काफी ग्रोथ भी हो रही है। इसके साथ ही हमें सर्विस सेक्टर में ग्रोथ लाने की आवश्यकता है और अगले पांच साल में इसे बढ़ाने के लिए काम करना है। इसकी शुरआत भी कर दी गयी है और अगले तीन साल के भीतर नवा रायपुर इनोवेशन तथा आईटी हब के रूप के जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बहुत ही जल्द कोर सेक्टर और सर्विस सेक्टर के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी शुरू होगी।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हमें ये जानकारी हैरानी होगी कि बड़े शहरों में उद्योगों से ज्यादा प्रदूषण सड़क पर चल रही वाहनों के जरिए होता है और इस पर नियंत्रण पाना बेहद जरुरी है। इसके लिए हम सभी को अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है और ये प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो पर्यावरण को संरक्षण करने में अपनी महती भूमिका निभाए।

छत्तीसगढ़ – विजन 2047 पर आयोजित इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री के सचिव तथा छत्तीसगढ़ सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव राहुल भगत ने कहा कि हमें ये सोचना होगा कि हमने अभी से तैयारी शुरू नहीं की तो साल 2047 तक भविष्य कैसा होगा। उन्होंने कहा कि जैसे प्रत्येक जीवित इंसान की सेहत उसके लिए जरूरी है वैसे ही पेड़ पौधों की अच्छी सेहत हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, उनके भीतर भी जीवन है और उनके जीवन से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। श्री भगत ने कहा कि आज तकनीक का दौर है और इसमें तेजी से बदलाव आ रहा है, लेकिन हमें इस बदलाव में भी पर्यावरण का ध्यान रखना होगा ताकि हम खुद और हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ और सुरक्षित रह सकें।

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग
कार्यालय मुख्य अभियंता
महानदी गोदावरी कछार, रायपुर (छ.ग.)
ई–प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना
eProcurement Portal: https://eproc.cgstate.gov.in

(द्वितीय आमंत्रण)

निम्नलिखित कार्यो के लिए दिनांक **01.04.2024 17:30** तक ऑन लाईन निविदाए आमंत्रित की जाती हैः

सिस्टम निविदा क्र निविदा सूचना क्र./ दिनांक	कार्य का नाम	अनुमानित लागत
सिस्टम निविदा क्र. **154151**/निविदा सूचना क्र. 59/वलेलि/2023–24, दुर्ग दिनांक 14.03.2024	दुर्ग जिले के विकासखण्ड दुर्ग की बिरेझर डायवर्सन शीर्ष कार्य का जीर्णोद्वार कार्य एवं आर.डी. 0 मी. से 3450 मी. तक माईनर एवं सब माईनर आर.डी. 0 मी. से 1050 मी. तक नहर लाईनिंग कार्य साथ ही 03 नग व्ही.आर.बी., 15 नग आउटलेट, 04 नग इनलेट निर्माण कार्य	**रू. 295.64 लाख** (दिनांक 01.08.2010 के एस.ओ.आर. तथा संशोधित 22.08.2022 के अनुसार)
सिस्टम निविदा क्र. **154152**/निविदा सूचना क्र. 60/वलेलि/2023–24, दुर्ग दिनांक 14.03.2024	दुर्ग जिले के विकासखण्ड दुर्ग की तांदुला परियोजना अंतर्गत खम्हरिया वितरक शाखा नहर की कोकड़ी माईनर का जीर्णोद्वार कार्य।	रू. 288.97 लाख (दिनांक 01.08.2010 के एस.ओ.आर. तथा संशोधित 22.08.2022 के अनुसार)

अन्य विवरण एवं विस्तृत निविदा छत्तीसगढ़ शासन की ई–प्रोक्योरमेंट वेब साइट https://eproc.cgstate.gov.in पर दिनांक **21.03.2024** समय 17.31 बजे से देखे तथा डाउनलोड़ किये जा सकते है।
नोट : निविदा में भाग लेने हेतु ठेकेदारों को ई–प्रोक्योरमेंट वेबसाईट https://eproc.cgstate.gov.in पर नामांकित/पंजीयन तथा लोक निर्माण विभाग की एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत ठेकेदार को उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन कराना अनिवार्य है।

कार्यपालन अभियंता
तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग
कृते मुख्य अभियंता महानदी गोदावरी कछार,
जल संसाधन विभाग, रायपुर, छ.ग.

जी - 08559/4

CAR DECOR
House Of Exclusive Seat Cover, Car Stereos Matting & Sun Control Film & Other Accessories
Shop No.3 Nafish Tower. Opp. Indian Coffee House, Akashganga, Bhilai
Mo.9300771925, 0788-4030919
K. Satyanarayan

ॐ SAIRAM Mobile Accessories
मोबाईल शॉप में कार्य करने हेतु लड़को की आवश्यकता है
7000415602
Shop No. 78, Himalaya Complex, Supela, Bhilai

ROCKEY INDUSTRIES FURNITURE PALACE
Deals in: (Steel & Wooden) Luxury & Imported Furniture
Akash Ganga, Supela, Bhilai Ph. 2296430

दास गार्मेन्ट्स
जींस, शर्ट, टी–शर्ट, फ्राक सूट, फ्राक, फैंसी सलवार सूट एवं किट्स वियर,अंडर गारमेन्ट्स, गाउन के लेटेस्ट कलेक्शन
एक बार अवश्य पधारें
गणेश मार्केट, गुरुद्वारा, रोड सुपेला, भिलाई, 7828248067

Ashok JEWELLERY
Gifts • Toys • Cosmetics Perfumes • Sia Jewellery
Beside Parakh Jewellers, Akash Ganga, Supela, Bhilai
Hello: 0788-4052727
Mukesh Jain 9009959111
Rishabh Jain 8103831329

पत्थर पटक कर प्रेमिका के पति को मार डालाः कत्ल के बाद लाश जलाई, नरमुंड-रीढ़ की हड्डियां बरामद

राजनांदगांव में पत्नी ने रची मर्डर की साजिश

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर पति को मार डाला। तीनों ने मर्डर के बाद लाश को पैरावट में डालकर आग लगा दी। पुलिस को कंकाल का सिर और रीढ़ की हड्डियां मिली थी। पूरा मामला डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के सहसपुर गांव का है।

दरअसल, 27 फरवरी को तीनों आरोपियों ने सुकालू राम कंवर (36) की हत्या कर लाश जलाई थी, जिसके बाद 12 मार्च को कंकाल का सिर और रीढ़ की हड्डियां मिली थी। पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि सहसपुर गांव का युवक सुकालू कंवर कुछ दिनों से लापता है, लेकिन पत्नी थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई है।

एसपी ने कहा कि मृतक सुकालू राम कंवर (36) की पत्नी केसर बाई कंवर पर पुलिस को शक था। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि प्रेमी मनेश उर्फ मनीष कंवर और उसके दोस्त जितेन्द्र उर्फ जीतू यादव के साथ साजिश रच हत्या की। इसके बाद शव को पैरावट में डालकर जला दिया।

पति बन रहा था प्यार में रोड़ा

आरोपी केसर बाई ने बताया कि वह अपने पति को रास्ते से हटाकर अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी। इसलिए अपने प्रेमी मनेश और उसके दोस्त जीतू को शादी समारोह में शामिल होने के बहाने बुलाया। इसके बाद मनेश, जीतू और सुकालू शराब लेने ग्राम कटली चले गए। वापस आकर तीनों ने शराब पी।

सिर पर पत्थर पटक कर और गला घोंटकर हत्या

इसके बाद अधिक नशा हो जाने के बाद जीतू ने सुकालू के सिर पर पत्थर पटक दिया, जिससे सुकालू लहूलुहान होकर बेहोश हो गया। मनेश ने गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी। मृतक की पत्नी के साथ मिलकर शव को पैरा में डालकर आग लगा दी।

पुलिस ने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के बाद की गिरफ्तारी

पुलिस ने बताया कि मिले कंकाल को डीएनए टेस्ट के लिए फोरेंसिक लैब रायपुर भेजा गया। डीएनए रिपोर्ट और सबूतों के आधार पर कंकाल की पहचान सुकालू कंवर निवासी सहसपुर के रूप में हुई। हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी केसर बाई कंवर, प्रेमी मनेश उर्फ मनीष (34) खैरागढ़ निवासी, जितेंद्र उर्फ जीतू यादव (32) घुमका निवासी को गिरफ्तार कर लिया है।

खास खबर

तालाब में डूबने से हुई बालक की मौतः दोस्तों के साथ नहाने गया था, पैर फिसलने से डूबा

भिलाई। दुर्ग जिले के खुर्सीपार के तालाब में नहाने गए एक बालक की डूबने से उसकी मौत हो गई। खबर लगते ही परिजन तालाब से निकाल कर उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची खुर्सीपार पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में लिया है।

जानकारी के मुताबिक, सुभाष मार्केट खुर्सीपार का रहने वाला डी नमन अपने कुछ दोस्तों के साथ नहाने के लिए डबरा पारा स्थित तालाब में गया था। जहां पहले तो सभी बच्चों ने जमकर पानी में मस्ती की और फिर जब नहाने लगे तो डी नमन का पैर अचानक से फिसल गया। पैर फिसलते ही डी नमन तालाब की गहराइयों में चला गया और डूबने लगा। डूबते ही डी नमन की सांसे उखड़ने लगी और वह बेहोश हो गया। उसके साथ गए सभी बच्चों ने उसे बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन बच्चों को तैरना नहीं आता था और आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर खुर्सीपार थाने की पुलिस टीम पहुंची और पानी में पूरी तरह डूब चुके डी नमन को बाहर निकाला।

दो अस्पतालों में बालक का किया चेकअप

खबर मिलते ही परिजन भी वहां पहुंच गए परिजनों ने उसे तत्काल पास के एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित दिया। परिजन उसे फिर सुपेला के शासकीय अस्पताल लेकर गए, जहां एक बार फिर डॉक्टरों ने चेकअप किया। वहां भी डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये सुनते ही मृत बालक की मां ने आपा खो दिया। फिलहाल परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

खुर्सीपार के मकान में मिला पीडीएस का 43 कट्टा चावलः खाद्य विभाग और पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई, जांच के लिए भेजा गया सैंपल

भिलाई। खुर्सीपार में खाद्य विभाग और खुर्सीपार पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर खुर्सीपार के एक घर से 43 कट्टा पीडीएस का चावल जब्त किया है। खाद्य विभाग ने सैंपल लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सैंपल की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद खुर्सीपार पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी।

जानकारी के मुताबिक, काली मंदिर मछली मार्केट के पास खुर्सीपार निवासी अमित मांझी के घर पर पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की। जहां 43 कट्टा पीडीएस का चावल बरामद हुआ। चावल को पकड़ने के बाद खाद्य विभाग के अधिकारियों ने उसे थाने में सुरक्षार्थ रखवाया है।

जांच के लिए भेजा गया सैंपल

चावल पीडीएस का ही है, इसकी पुष्टि के लिए सैंपल ले लिया है। सैंपल को जांच के लिए भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट आने के बाद खुर्सीपार पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी।

बता दें कि दुर्ग जिले में बड़े पैमाने पर पीडीएस के चावल की तस्करी होती है। इसके पहले भी खुर्सीपार और सुपेला थाना में पीडीएस के चावल की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। वहीं करीब 10 दिन पहले जामुल पुलिस ने भी पीडीएस का चावल जब्त किया था। इसके बाद अब खुर्सीपार क्षेत्र में फिर से पीडीएस का चावल जब्त किया गया है।

सेक्टर-6 एंव रिसाली के प्रतिष्ठित संस्थान विज्ञापन के लिए संपर्क करें:-
9303289950, 9827806026

भिलाई की सबसे बड़ी चुड़ी की दुकान
निखार बैंगल
मो.- 9826186026
Shop-47, 'A' Market, Sec-6, Bhilai Nagar, Distt., Durg (C.G.)

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

ई–मेलः mandi.durg.cg@gmail.com

Azadi Ka Amrit Mahotsav

क्रमांक/मंडी/निर्माण/दुर्ग/2023–24/ 1728 दुर्ग.दिनांक– 14/03/2024

–:: मैन्युअल निविदा आमंत्रण सूचना ::–

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति–दुर्ग जिला–दुर्ग (छ.ग.) के अंतर्गत निम्न दर्शित कार्य/स्थल एवं कार्य के सम्मुख दर्शित लागत अनुसार कार्य कराये जाने हेतु **छ.ग.लोक निर्माण विभाग में एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत** सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से मुहरबंद निविदाएँ केवल पंजीकृत डाक से तीन लिफाफा पद्धति से दिनांक–25.04.2024 को सायं 05.30 बजे तक **छ.ग.शासन लो.नि.वि. भवन/सड़क कार्य हेतु दिनांक–01.01.2015 से एवं विद्युत कार्य हेतु दिनांक–01.07.2015** से प्रभावशील एसओआर एवं इस निविदा के जारी दिनांक तक संशोधित दर अनुसूची के आधार पर निविदा प्रपत्र–अ (प्रतिशत दर) में सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति–दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ.ग.) में आमंत्रित की जाती है । प्राप्त निविदाएँ इस कार्यालय में उपस्थित ठेकेदारों/प्रतिनिधियों के समक्ष दिनांक–30.04.2024 को दोपहर 02.00 बजे खोली जावेगी ।

1–निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि :– 12.04.2024 को सायं 05.30 बजे तक
2–निविदा प्रपत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि :– 25.04.2024 को सायं 05.30 बजे तक
3–निविदा प्रपत्र खोले जाने की प्रारंभिक तिथि :– 30.04.2024 को दोप. 02.00 बजे से

कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	निर्माण कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू.लाख में)	अमानत की राशि लाख रू. में	ठेकेदार की श्रेणी	समयावधि (वर्षाऋतु सहित)	निविदा प्रपत्र का मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
1	ग्राम उरला में किसान भवन निर्माण कार्य	19.56	14700/–	"द" एवं उच्च	06 माह	1000/–
2	ग्राम बघेरा में किसान भवन निर्माण कार्य	19.56	14700/–	"द" एवं उच्च	06 माह	1000/–
3	ग्राम पुलगॉव में किसान भवन निर्माण कार्य	19.56	14700/–	"द" एवं उच्च	06 माह	1000/–
4	ग्राम करहीडीह में किसान भवन निर्माण कार्य	19.56	14700/–	"द" एवं उच्च	06 माह	1000/–
5	ग्राम पोटिया में किसान भवन निर्माण कार्य	19.56	14700/–	"द" एवं उच्च	06 माह	1000/–
6	ग्राम बोरसी में किसान भवन निर्माण कार्य	19.56	14700/–	"द" एवं उच्च	06 माह	1000/–
7	ग्राम उरला में विभिन्न गलियों में सी.सी.रोड निर्माण कार्य	19.35	14600/–	"द" एवं उच्च	03 माह	1000/–
8	ग्राम बघेरा में विभिन्न गलियों में सी.सी.रोड निर्माण कार्य	19.35	14600/–	"द" एवं उच्च	03 माह	1000/–
9	ग्राम पुलगॉव में विभिन्न गलियों में सी.सी.रोड निर्माण कार्य	19.35	14600/–	"द" एवं उच्च	03 माह	1000/–
10	ग्राम करहीडीह में विभिन्न गलियों में सी.सी.रोड निर्माण कार्य	19.35	14600/–	"द" एवं उच्च	03 माह	1000/–
11	ग्राम पोटिया में विभिन्न गलियों में सी.सी.रोड निर्माण कार्य	19.35	14600/–	"द" एवं उच्च	03 माह	1000/–
12	ग्राम बोरसी में विभिन्न गलियों में सी.सी.रोड निर्माण कार्य	19.35	14600/–	"द" एवं उच्च	03 माह	1000/–
13	वि.स.क्षेत्र अहिवारा, वि.ख.–धमधा, ग्राम सेमरिया (गि.) में 09 नग व्यावसायिक परिसर निर्माण कार्य	19.90	15000/–	"द" एवं उच्च	06 माह	1000/–
14	वि.स.क्षेत्र अहिवारा, वि.ख.–धमधा, ग्राम झेंझरी पंचायत करंजा भिलाई में किसान भवन निर्माण कार्य	9.80	7400/–	"द" एवं उच्च	06 माह	1000/–
15	वि.स.क्षेत्र अहिवारा, वि.ख.–दुर्ग, अंतर्गत ग्राम बासीन में डोम शेड मंच निर्माण कार्य	6.37	4800/–	"द" एवं उच्च	04 माह	1000/–
16	वि.स.क्षेत्र अहिवारा, वि.ख.–धमधा, ग्राम अंतर्गत ग्राम सुरजीडीह पंचायत मुर्रा में डोम शेड मंच निर्माण कार्य	6.37	4800/–	"द" एवं उच्च	04 माह	1000/–
17	वि.स.क्षेत्र अहिवारा, वि.ख.–दुर्ग, अंतर्गत ग्राम नंदकठ्ठी में गोपाल तिवारी के घर से तालाब तक 1200 वर्ग मीटर सी.सी.रोड निर्माण कार्य	10.60	8000/–	"द" एवं उच्च	03 माह	1000/–
18	वि.स.क्षेत्र अहिवारा, वि.ख.–धमधा, अंतर्गत ग्राम नंदिनी–खुंदनी में रामसाय पाल के घर से कलीराम के घर तक 1200 वर्ग मीटर सी.सी.रोड निर्माण कार्य	10.98	8300/–	"द" एवं उच्च	03 माह	1000/–
19	वि.स.क्षेत्र अहिवारा, वि.ख.–धमधा, अंतर्गत ग्राम मेडेसरा में डोम शेड मंच निर्माण कार्य	13.11	9900/–	"द" एवं उच्च	04 माह	1000/–
20	वि.स.क्षेत्र अहिवारा, वि.ख.–धमधा, अंतर्गत ग्राम नारधा में डोम शेड मंच निर्माण कार्य	9.71	7300/–	"द" एवं उच्च	04 माह	1000/–
21	वि.स.क्षेत्र अहिवारा, वि.ख.–धमधा, अंतर्गत ग्राम कोडिया में गुरूघासी दास मंदिर के पास 1200 वर्ग मीटर सी.सी.रोड निर्माण कार्य	10.83	8200/–	"द" एवं उच्च	03 माह	1000/–
22	वि.स.क्षेत्र अहिवारा, वि.ख.–दुर्ग, अंतर्गत ग्राम बोड़ेगॉव में हाटबाजार निर्माण कार्य	19.42	14600/–	"द" एवं उच्च	04 माह	1000/–
23	वि.स.क्षेत्र अहिवारा, वि.ख.–पाटन, अंतर्गत ग्राम सिरसाकला में डोम शेड मंच निर्माण कार्य	9.71	7300/–	"द" एवं उच्च	04 माह	1000/–
24	वि.स.क्षेत्र अहिवारा, वि.ख.–धमधा, अंतर्गत ग्राम नंदिनी–खुंदिनी में शमशान घाट रोड तक 1760 वर्ग मीटर सी.सी.रोड निर्माण कार्य	16.10	12100/–	"द" एवं उच्च	03 माह	1000/–
25	वि.स.क्षेत्र अहिवारा, वि.ख.–धमधा, अंतर्गत ग्राम कोड़िया में सगनी चौक के पास 09 नग व्यावसायिक परिसर निर्माण कार्य	19.90	15000/–	"द" एवं उच्च	06 माह	1000/–
26	वि.स.क्षेत्र अहिवारा, वि.ख.–धमधा, अंतर्गत ग्राम कपसदा में भगवान दिन के बाडा से ग्राम पंचायत भवन तक 2120 वर्ग मीटर सर.सी.रोड निर्माण कार्य	19.39	14600/–	"द" एवं उच्च	03 माह	1000/–
27	वि.स.क्षेत्र अहिवारा, वि.ख.–धमधा, अंतर्गत ग्राम नारधा में नंदी मैदान से पटेल भवन मार्ग तक 1480 सी.सी. रोड निर्माण कार्य	13.54	10200/–	"द" एवं उच्च	03 माह	1000/–
28	मंडी प्रांगण की बाउण्ड्रीवाल का विशेष मरम्मत कार्य	13.45	10100/–	"द" एवं उच्च	03 माह	1000/–
29	मंडी प्रांगण में नाली निर्माण कार्य	19.31	14500/–	"द" एवं उच्च	04 माह	1000/–
30	मंडी प्रांगण के 56 नग दुकानों में शौचालय मरम्मत कार्य	6.21	4700/–	"द" एवं उच्च	02 माह	1000/–
31	मंडी प्रांगण के मुख्य कार्यालय के सामने सौन्दर्यीकरण एवं उद्यान निर्माण कार्य	13.72	10300/–	"द" एवं उच्च	02 माह	1000/–
32	मंडी प्रांगण में सायकल पार्किंग स्टैण्ड निर्माण कार्य	8.57	6500/–	"द" एवं उच्च	04 माह	1000/–
33	मंडी प्रांगण दुर्ग में ह्यूम पाईप 900 एम.एम. डाया कल्वर्ट निर्माण कार्य	3.61	3700/–	"द" एवं उच्च	02 माह	1000/–
34	अण्डा में समिति से रेस्ट हाउस तक 100 मीटर सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य	4.85	4900/–	"द" एवं उच्च	03 माह	1000/–
35	अण्डा में धान खरीदी केन्द्र में 02 नग शेड निर्माण कार्य	19.40	19600/–	"द" एवं उच्च	04 माह	1000/–
36	विनायकपुर में व्यावसायिक परिसर में 05 कमरा का निर्माण कार्य	19.43	14600/–	"द" एवं उच्च	06 माह	1000/–
37	गनियारी में मेन रोड से बाजार तक 100 मीटर सी.सी.रोड निर्माण कार्य	4.85	4900/–	"द" एवं उच्च	03 माह	1000/–
38	गनियारी में बाजार में 05 चबूतरा निर्माण कार्य	11.60	8700/–	"द" एवं उच्च	03 माह	1000/–
39	कोलिहापुरी में मेन रोड से हाटबाजार तक 200 मीटर सी.सी.रोड निर्माण कार्य	5.84	4400/–	"द" एवं उच्च	03 माह	1000/–
40	अछोटी में व्यावसायिक परिसर में 05 कमरा का निर्माण कार्य	19.43	14600/–	"द" एवं उच्च	06 माह	1000/–
41	अछोटी में सांस्कृतिक मंच में डोम शेड निर्माण	14.55	11000/–	"द" एवं उच्च	04 माह	1000/–
42	कुथरेल में धान खरीदी केन्द्र में 02 नग चबूतरा निर्माण कार्य	19.40	19600/–	"द" एवं उच्च	04 माह	1000/–
43	झोला में शिवाजी चौक के पास डोम शेड निर्माण	14.55	11000/–	"द" एवं उच्च	04 माह	1000/–
44	रसमड़ा में दशहरा मैदान में सामुदायिक भवन निर्माण	9.71	7300/–	"द" एवं उच्च	06 माह	1000/–
45	कोनारी में आबादी पारा में सामुदायिक भवन निर्माण	9.71	7300/–	"द" एवं उच्च	06 माह	1000/–
46	आमटी में विभिन्न गलियों में सी.सी.रोड निर्माण	9.71	7300/–	"द" एवं उच्च	03 माह	1000/–
47	बिरेझर में व्यावसायिक परिसर में 05 कमरा का निर्माण कार्य	19.43	14600/–	"द" एवं उच्च	06 माह	1000/–
48	भोथली में हनुमान मंदिर के पास डोम शेड निर्माण	14.55	11000/–	"द" एवं उच्च	04 माह	1000/–
49	कोटनी में विभिन्न गलियों में सी.सी.रोड निर्माण	9.71	7300/–	"द" एवं उच्च	03 माह	1000/–
50	खोपली में सामुदायिक कुर्मी भवन निर्माण	14.54	11000/–	"द" एवं उच्च	06 माह	1000/–
51	बोरीगारका में आबादी पारा में सांस्कृतिक मंच निर्माण	6.37	4800/–	"द" एवं उच्च	04 माह	1000/–
52	आमटी में आबादी पारा में 100 मीटर सी.सी.रोड निर्माण	3.87	3900/–	"द" एवं उच्च	03 माह	1000/–
53	आमटी में गली के दोनों साईड नाली निर्माण	4.90	4900/–	"द" एवं उच्च	02 माह	1000/–
54	चंदखुरी में गोड़पारा में सामुदायिक भवन निर्माण	6.37	4800/–	"द" एवं उच्च	06 माह	1000/–
55	खाडा में आदिवासी पारा में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	6.37	4800/–	"द" एवं उच्च	06 माह	1000/–
56	डुमरडीह में वार्ड–10 एवं 11 में सांस्कृतिक मंच निर्माण कार्य	9.71	7300/–	"द" एवं उच्च	04 माह	1000/–
57	खुरसूल में सी.सी.रोड राजू साहू के घर से मुख्य सड़क तक निर्माण कार्य	4.38	4400/–	"द" एवं उच्च	03 माह	1000/–
58	खुरसूल में विष्णु मेश्राम से त्रिवेणी घर तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य	3.87	3900/–	"द" एवं उच्च	03 माह	1000/–
59	बोरई में नवीन सार्वजनिक मंच निर्माण वार्ड क्र.–01 में	6.37	4800/–	"द" एवं उच्च	04 माह	1000/–
60	बिरेझर में तालाब के पास दशगात्र शेड निर्माण	4.59	4600/–	"द" एवं उच्च	02 माह	1000/–
61	हनोदा में वार्ड क्र.–20 में सांस्कृतिक मंच एवं एक कमरा निर्माण कार्य	9.71	7300/–	"द" एवं उच्च	04 माह	1000/–
62	घुघसीडीह में दुर्गा मंच निर्माण / सी.सी.रोड दुर्गा मंच से पीपल चबूतरा तक	10.25	7700/–	"द" एवं उच्च	04 माह	1000/–
63	चिंगरी में सी.सी.रोड अनुज देशमुख के घर से मेन रोड तक निर्माण कार्य	4.38	4400/–	"द" एवं उच्च	03 माह	1000/–
64	कोतरो में राशन दुकान के पास शेड निर्माण	14.55	11000/–	"द" एवं उच्च	03 माह	1000/–
65	मोहलाई में यादव समाज हेतु भवन निर्माण	9.80	7400/–	"द" एवं उच्च	06 माह	1000/–
66	झोला में शिवाजी की स्थल पर मंच निर्माण कार्य	6.37	4800/–	"द" एवं उच्च	03 माह	1000/–
67	डुमरडीह में सार्वजनिक भवन घीवर पारा में	6.37	4800/–	"द" एवं उच्च	06 माह	1000/–
68	धनोरा में सी.सी.रोड निर्माण मन्नम नगर कॉलोनी प्रभाकरण घर से दिव्य प्रकाश मिश्रा तक	4.85	4900/–	"द" एवं उच्च	03 माह	1000/–

1– निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के लिये वैद्य पंजीयन, बैंक साल्वेंसी (एक साल से पुराना न हो एवं अनुमानित लागत का 15 प्रति. की मूल्य का), जी.एस.टी. पंजीयन, पेन कार्ड की मूल प्रति अवलोकनार्थ तथा आवेदन सहित समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति प्रस्तुत करने के उपरांत दिनांक–12.04.2024 तक कार्यालयीन समय में निर्धारित शुल्क रूपये 1000/– की नगद राशि जमा कर प्राप्त किये जा सकते है ।

2– अमानत की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी एफ.डी.आर./टी.डी.आर. या डाक विभाग द्वारा जारी एन.एस.सी. के रूप में सचिव कृषि उपज मंडी समिति दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ.ग.) को देय ही स्वीकार्य होगी ।

3– अन्य शर्ते एवं कार्य से संबंधित जानकारी कार्यालय में कार्यालयीन समय में दिनांक–12.04.2024 तक देखे/प्राप्त किये जा सकते है, जो कि इस निविदा अनुबंध का अनिवार्य भाग है ।

4– इस आमंत्रित निविदा अनुसार उपरोक्य कार्यो के लिए निविदा दर प्रस्तुतीकरण के संदर्भ में लोक निर्माण विभाग छ.ग.शासन का परिपत्र क्रमांक–625/3675/टी/11/19/निविदा रायपुर दिनांक–05.03.2011 द्वारा प्रभावशील नियम लागू/प्रभावशील है ।

5– उपरोक्त कार्य हेतु यदि निविदाकार द्वारा लागू दर/दर अनुसूची में 10 प्रतिशत से कम दर कोट किया जाता है तो निविदा हेतु स्पेशल शर्ते लागू होगी । तदानुसार अंतर की राशि सचिव कृषि उपज मंडी समिति दुर्ग के नाम एफ.डी.आर. के रूप में अनुबंध निष्पादन के पूर्व जमा करना होगा । शर्ते की प्रति निविदाओं के साथ प्रदाय की जायेगी ।

6– लिफाफा–"अ" में ई.एम.डी. एवं शपथपत्र, लिफाफा–"ब" में निविदा प्रपत्र एवं समस्त दस्तावेज (वैद्य पंजीयन, बैंक साल्वेंसी, जी.एस.टी. पंजीयन पेन कार्ड) की मूलप्रति की छायाप्रति तथा लिफाफा–"स" में लिफाफा–"अ" एवं "ब" प्रस्तुत किया जायेगा एवं लिफाफा–"स" में कार्य का नाम का उल्लेख करें ।

सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति दुर्ग
जिला–दुर्ग (छ.ग.)

भारसाधक अधिकारी,
कृषि उपज मण्डी समिति दुर्ग
जिला–दुर्ग (छ.ग.)

S-40101/3

दुल्हन बैंगल्स & फैंसी
RAKESH SINGH
Mob.-9840760388
7987759030
Specialist : Wedding mix match bangles, Glass bangle, Plastic bangle. Saree pin, Bindi, Rubber Band. Bracelet, Butter Fly, Ear ring and many more
पुष्पांजलि स्वीट्स के बाजू में, कृष्णा टाकिज रोड, रिसाली, भिलाई

भारतीय बैग हाउस
फैंसी स्ट्राली, स्कूल बैग, ऑफिस बैग, सफर बैग, लेपटॉप बैग, फैंसी छतरी, रेनकोट इत्यादि के विक्रेता
VIP happy journey
AMERICAN TOURISTER
कृष्णा टाकीज रोड, बैंक ऑफ बडौदा के बाजू में रिसाली भिलाई, संजय गुप्ता: 93003-77572

भिलाई मसाला उद्योग
शुद्ध कुटे हुए मसाले,पापड़, अचार, बड़ी, जड़ी-बूटी, जचकी का सामान इत्यादि
128, ए- मार्केट, सेक्टर-6, भिलाई, फोन. 2284508, मो. 9826137766

राकेश ट्रेडर्स
विगत 6 वर्षो से यह दुकान पानी टंकी के सामने स्थानांतरित हो गई है।
Dealers
Marbles, Grinight, Black Stone, Nano & Double Charge Verified Tiles Digital Wall & Floor Tiles Cement Coloru etc.
रायपुर रेट पर माल उपलब्ध
Rakesh Sahu
9302443750, 9907127357
Krishna Talkies Road, Beside Hariom Furniture, Risali, Bhilai - 490006

खास - खबर

प्लेट मिल ने दैनिक उत्पादन का बनाया नया कीर्तिमान

भिलाई। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र की प्लेट मिल, जिसका हाल ही में 45 दिनों का वृहद कैपिटल रिपेयर पूरा हुआ, ने 14 मार्च 2024 को 901 स्लैब से 6,680 टन प्लेटों की रोलिंग कर दैनिक उत्पादन का नया कीर्तिमान बनाया है। मिल ने 21 अक्टूबर 2023 को हासिल किए गए 6,532 टन के पिछले दैनिक रिकॉर्ड को पार कर लिया है। कैपिटल रिपेयर के दौरान, रफिंग स्टैंड और फिनिशिंग स्टैंड की मशीनिंग के द्वारा त्रुटियों को सुधारा गया। इस रिपेयर के बाद, मिल ने 8 मिलीमीटर मोटाई की प्लेटों की रोलिंग का काम शुरू किया जिनका उत्पादन पिछले तीन वर्षों से बंद था। 11 मार्च 2024 को मिल ने 8 मिमी मोटाई के 110 टन प्लेटों की रोलिंग की। भिलाई इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी अनिर्बान दासगुप्ता ने टीम प्लेट मिल, स्टील मेल्टिंग शॉप-2 और संबंधित शॉप्स को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी तथा उन्हें आगे भी श्रेष्ठ प्रदर्शन जारी रखने का आग्रह किया। कार्यपालक निदेशक (वर्क्स) अंजनी कुमार ने सुरक्षा, गुणवत्ता व समयबद्धता को प्राथमिकता देते हुए रिकॉर्ड उत्पादन हेतु प्लेट मिल नेतृत्व की प्रशंसा की तथा सभी संबंधित विभागों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए उत्पादन लक्ष्य हासिल करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी प्लेट मिल बिरादरी को उत्पादन में नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए बधाई दी है। उन्होंने स्टील मेल्टिंग शॉप-2 को कास्ट स्लैब की निरन्तर आपूर्ति, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल विभाग तथा रिसर्च एंड कंट्रोल लेबोरेटरी सहित संबंधित शॉप्स को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया, जिसके बिना यह रिकॉर्ड उत्पादन संभव नहीं था।

आम, फलबहार की नीलामी एक अप्रैल को

दुर्ग। जिले की शासकीय उद्यान रोपणी रूआबांधा के आम, फलबहार (चौसठ पौधे) की नीलामी एक अप्रैल 2024 को शासकीय उद्यान रोपणी रूआबांधा में किया जाएगा। इच्छुक व्यापारी विस्तृत जानकारी के लिए रूआबांधा रोपणी के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

मृतक के परिजनों को मिली 12 लाख रुपए की आर्थिक सहायता

दुर्ग। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने दुर्घटना में मृतक के परिजनों को 12 लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पथरिया थाना बोरी जिला दुर्ग निवासी श्रीमती नागेश्वरी निषाद की विगत 10 जुलाई 2023 को आग स जल जाने से मृत्यु हो गयी थी। इसी प्रकार ग्राम कोपेडीह, तहसील पाटन जिला दुर्ग निवासी ओमप्रकाश देवांगन की विगत 24 मई 2022 को नदी के पानी में डूबने से मृत्यु हो गयी थी। कलेक्टर द्वारा शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के प्रावधानों के अनुरूप स्व. श्रीमती नागेश्वरी निषाद के पति मनोज केंवट को, स्व. ओमप्रकाश देवांगन की माता श्रीमती नंदनी देवांगन को, स्व. दानेश्वर गोस्वामी के पिता द्वारिकापुरी गोस्वामी को एवं स्व. आयान हुसैन के पिता मोहम्मद शकील को 4-4 लाख रूपये अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

मां रेणुका यलम्मा जात्रा में झूमे श्रद्धालु, समाज के लिए विधायक रिकेश ने की बड़ी घोषणा

मां मंकिनम्मा मंदिर परिसर के चारों ओर होगी फेंसिंग, सामुदायिक भवन के लिए मिलेंगे विधायक निधि से पांच लाख रुपए

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। श्रीश्रीश्री मां मंकिनम्मा सेवा समिति द्वारा मां रणुका यलम्मा जात्रा समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर समाज के श्रद्धालुओं ने भव्य शोभायात्रा (जात्रा) निकाली गई। यह शोभायात्रा आंध्रा स्कूल ग्राउंड कैंप-1 से निकाली गई जो मां मंकिनम्मा मंदिर, जवाहर नगर तक पहुंची। मंकिनम्मा मंदिर परिसर में भव्य समारोह का आयोजन किया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन उपस्थित रहे।

मां रणुका यलम्मा जात्रा समारोह की शुरुआत सुबह 9 बजे हुई। जात्रा में विभिन्न प्रकार की झांकियों का समावेश किया गया। माता के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं पदयात्रा करते हुए मां मंकिनम्मा मंदिर परिसर पहुंचे। मंदिर परिसर में सम्मान समारोह व विशाल भंडारा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि विधायक रिकेश सेन ने समाज के लोगों का अभिनंदन किया और मां मंकिनम्मा के दर्शन कर उनकी विधिवत पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित बुजुर्ग का आशीर्वाद लिया और बच्चों के साथ थोड़ी हंसी ठिठोली की।

विधायक रिकेश ने की पांच लाख रुपए देने की घोषणा

कार्यक्रम के दौरान समाज के प्रतिनिधियों ने विधायक रिकेश सेन का महा पुष्पहार से स्वागत व सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विधायक रिकेश सेन ने समाज के लोगों के लिए बड़ी घोषणा की। विधायक रिकेश सेन ने कहा कि मां मंकिनम्मा का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है। आप सभी के सहयोग व मां के आशीर्वाद से आज आपकी सेवा में हूं। उन्होंने कहा कि समाज के लोगों ने मंदिर के चारो ओर फेंसिंग कराने की मांग की है। मंच से विधायक रिकेश सेन ने मंदिर के चारों ओर फेंसिंग कराने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने यहां एक सामूदायिक भवन निर्माण के लिए विधायक निधि से पांच लाख रुपए देने की घोषणा भी की। विधायक रिकेश की घोषणा का सभी समाज के लोगों ने आभार जताया। इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन में श्रीश्रीश्री मां मंकिनम्मा सेवा समिति के संयोजक संयोजक एम. जगपति राव, समाज सेवी निरज सिंह, विधायक प्रतिनिधि लक्ष्मण चौधरी, अध्यक्ष यू. गणपति राव, महासचिव एल काली दास व कोषाध्यक्ष एम अनंत राव का विशेष योगदान रहा।

खुर्सीपार क्षेत्र के सीवर लाईन, चेम्बर निर्माण कार्य का रास्ता खुला

भिलाई निगम के महापौर परिषद ने दी स्वीकृति

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। खुर्सीपार के बरसो पुराने सीवरेज लाईन एवं चेम्बर निर्माण कार्य की स्वीकृति सहित भिलाई के विभिन्न खेल मैदानों के संधारण, संचालन एवं रखखाव के लिए रूचि की अभिव्यक्ति बुलाये जाने तथा स्वच्छता श्रृंगार योजनांतर्गत सामुदायिक शौचालय के रख रखाव एवं संचालन कार्य के अवधि में वृद्धि किये जाने के प्रस्ताव को भिलाई निगम के महापौर परिषद ने दी स्वीकृति।

महापौर परिषद की बैठक महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता एवं आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव, अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में जोन-4 शिवाजी नगर खुर्सीपार में सीवर लाईन एवं चेम्बर निर्माण कार्य लागत राशि 7 करोड 29 लाख 90 हजार कुल तीन भाग मे कार्य कराये जाने हेतु सदस्यो ने विस्तृत चर्चा कर सीवरेज जैसे जनहितकारी अतिआवश्यक कार्य को ध्यान में रखते हुए कार्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इसी प्रकार केम्प-2 तालाब सौंदर्यीकरण अंतर्गत रिटेनिंग वॉल, उद्यान विकास, विद्युत व्यवस्था के साथ तालाब का सिल्ट, मलबा सफाई एवं परिवहन जन सहभागिता से कराये जाने के प्रस्ताव पर विचार पश्चात निविदा के माध्यम से विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

निगम के सभी जोन क्षेत्र में संचालित सामुदायिक शौचालय के रखरखाव एवं संचालन शासन के स्वच्छता श्रृंगार योजना के तहत वर्तमान एन.जी.ओ. एवं स्व सहायता समूह के कार्यो के गुण-दोष के आधार पर समय वृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में हाउसिंग बोर्ड काली बाड़ी चौक से भगवा चौक के सड़क चौड़ीकरण कार्य हेतु ट्रांसफार्मर एवं विद्युत पोल को हटाये जाने, जोन-2 के अंतर्गत शांति नगर दशहरा मैदान, जवाहर नगर स्पोर्ट्स काम्पलेक्स,हाउसिंग बोर्ड क्रिकेट मैदान तथा जोन-3 के सेक्टर 2 फूटबाल मैदान का संचालन, संधारण एवं रखरखाव हेतु संस्था से रूचि की झअभिव्यक्ति मंगवाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। महापौर परिषद के सदस्य सीजू एन्थोनी, लक्ष्मीपति राजू, केशव चौबे, संदीप निरंकारी, लालचंद वर्मा, साकेत चंद्राकर, आदित्य सिंह, चन्द्रशेखर गंवई, मन्नान गफ्फार खान, एकांश बंछोर, रीता सिंह गेरा, नेहा साहू सहित विभागीय सचिव एवं अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

जिले के 6 खिलाड़ियों को शहीद राजीव पाण्डेय खेल पुरुस्कार से नवाजा गया

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। छत्तीसगढ़ राज्य खेल अलंकरण 2024 मे छत्तीसगढ़ नेटबॉल के दुर्ग जिले के 6 खिलाड़ियों को वर्ष 2020-2021 के लिए शहीद राजीव पाण्डेय खेल पुरुस्कार से नवाज़ा गया, यह सभी खिलाडी जिला दुर्ग के भिलाई नगर के निवासी है।

इन खिलाड़ियों ने वर्ष 2019-2020 मे आयोजित 37वी सीनियर राष्ट्रीय नेटबॉल प्रतियोगिता (पुरुष) मे छत्तीसगढ़ के लिए कस्य पदक प्राप्त किया,वही वर्ष 2020-2021 मे 38वी सीनियर राष्ट्रीय नेटबॉल प्रतियोगिता (पुरुष) मे अपने खेल के आधार पे छत्तीसगढ़ का लोहा मनवाते हुए स्वर्ण पदक प्राप्त किया।

इनकी उपलब्धियों के लिए छत्तीसगढ़ खेल एवं युवा कलयाण विभाग द्वारा शहीद राजीव पाण्डेय पुरुस्कार से सम्मानित किया गया। सम्मान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के नाम.(1). प्रशांत जेकब (2).नीलेश शर्मा (3). प्रकाश विश्वकर्मा (4). इमरान खान (5). मनोज साहू (6). मोहन राव है।

135 करोड़ 34 लाख 90 हजार का बजट पारित, जनता के हित और विकास में टेक्नोलॉजी का उपयोग - महापौर

श्रीकंचनपथ न्यूज

रिसाली। रिसाली महापौर शशि सिन्हा ने शुक्रवार को 135 करोड़ 34 लाख 90 हजार का 2024-25 के लिए बजट प्रस्तुत की। वे ठीक 10:15 बजे सदन पहुंची। महापौर द्वारा लगभग 15 मिनट के बजट अभिभाषण प्रस्तुत करने के बाद सभापति केशव बंछोर ने विशेष सभा में बजट संकल्प पारित कराया। महापौर ने 6.91 लाख लाभ का बजट बताया। सत्ता पक्ष के पार्षदों ने सदन में पहले हाथ उठाया फिर बजट के समर्थन में मेज थप थपाकर ध्वनी मत से पारित किया।

महापौर शशि सिन्हा ने अपने बजट अभिभाषण में कहा कि गत वर्षों में रिसाली शहर में अपनी उदयगामी पहचान बनाई है और हम रिसाली को उच्चस्तरीय शहरों के रूप में पहचान दिलाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जनता के हित और विकास में टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। इसके लिए रिसाली निगम और स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्व विद्यालय के बीच एक अनुबंध किया जा रहा है। इस अनुबंध के तहत रिसाली निगम क्षेत्र की जनता के लिए सुविधा डेवलप करेंगे। उन्होंने बताया कि इस विषय को लेकर स्वयं और सभापति केशव बंछोर कुलपति एम.के.वर्मा से चर्चा भी कर चुके है। बजट के लिए बुलाए गए विशेष सभा में महापौर परिषद के सद्स्य चन्द्रभान सिंह ठाकुर, गोविन्द चतुर्वेदी, सनीर साहू, परमेश्वर कुमार, सोनिया देवांगन नेता प्रतिपक्ष शैलेन्द्र साहू आदि उपस्थित थे।

बजट अभिभाषण के बाद सभापति केशव बंछोर ने पार्षदों को चर्चा के लिए आमंत्रित किया। नेता प्रतिपक्ष शैलेन्द्र साहू समेत पार्षद धर्मेन्द्र भगत, विधि यादव, हरीशचंद्र, खिलेन्द्र चन्द्राकर व सविता ढवस, रमा साहू ने सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास किया। बाद में सभापति ने बहुमत के आधार पर बजट संकल्प पारित किए जाने की घोषणा की।

एक नजर आय व्यय पर

अनुमानित बजट - 13534.90
राजस्व आय - 5225.06
पूंजीगत प्राप्तिया - 8309.84
राजस्व व्यय - 5221.80
पूंजीगत व्यय - 8306.30

मुक्तिधामों के कायाकल्प के लिए विधायक गजेंद्र यादव एवं महापौर धीरज बाकलीवाल ने किया भूमिपूजन

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत शहर के मुक्तिधामों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। मुक्तिधाम परिसर में शेड निर्माण,बाउंड्रीवाल,सहित विभिन्न अन्य कार्य एवं पेयजल तथा बैठक व्यवस्था दुरुस्त किया जायेगा। शोक सांत्वना देने हॉल बनाया जाएगा।

एक साथ दुर्ग शहर विधानसभा क्षेत्र के 8 मुक्तिधाम परिसर पर होने वाले कार्य के लिए आज विधायक गजेंद्र यादव,महापौर धीरज बाकलीवाल एवं रजनी विजय बघेल, के मुख्य अतिथि में भूमिपूजन किया गया।कार्यक्रम के दौरान सभापति राजेश यादव,आयुक्त लोकेश चन्द्राकर,लोक कर्म प्रभारी अब्दुल गनी,संजय कोहले,नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा,

साहू,उपनेता प्रतिपक्ष देवनारायण चन्द्राकर,भोला महोबिया,शिवेंद्र परिहार,अरुण सिंह,नरेंद्र बंजारे,जमुना,पार्षदगण उपास्थिति थे।विधायक गजेंद्र यादव के प्रयासों से शहर के मुख्य 8 स्थानों में मुक्तिधामों के कायाकल्प के लिए शासन से 2.48 करोड़ की स्वीकृति कराई,स्वीकृति मिलने के बाद किये गए भूमिपूजन के तहत वार्ड 15 करहीडीह, वार्ड 17 कादम्बरी नगर, वार्ड विद्युत सब स्टेशन के सामने, वार्ड 56 बघेरा, वार्ड 57 उरला, वार्ड 60 रायपुर नाका, वार्ड 11 हरनाबाँधा एवं वार्ड 50 बोरसीभाठा के मुक्तिधाम शामिल है।इन मुक्तिधामों में बाउंड्रीवॉल,बारिश के सीजन में कीचड़ से बचने पेवर ब्लॉक, शवदाह गृह शेड रिपेयरिंग, शवदाह गृह के नए शेड निर्माण,शोक सभा के लिए सभागृह,शौचालय, बैठने के लिए चबूतरा, पेयजल व्यवस्था, सहित अन्य निर्माण कार्य होंगे। वार्ड 11 में मुक्तिधाम जीर्णोद्धार कार्य करने भुमिपूजन किया गया। विधायक गजेंद्र यादव उक्त कार्य अतिशीघ्र प्रारंभ कर गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाये।उन्होंने कहा कि इसी प्रकार विकास कार्य प्राथमिकता के आधार पर शहर में कराए जाएंगे।इस अवसर पर विधायक गजेंद्र यादव व महापौर धीरज बाकलीवाल का पार्षद एवं स्थानीय लोगो ने आभार व्यक्त किया।

नरेश तेजवानी,कविता तांडी,काशीराम कोसरे, खिलावन मटियारा,सतीश देवांगन, अमित देवांगन,बिजेंद्र भारद्वाज,बृजलाल पटेल,अजित वैध,चमेली साहू,कुमारी साहू,कार्यपालन अभियंता दिनेश नेताम, सहायक अभियंता आर.के. पलिया, सहायक अभियंता गिरीश दीवान, सजय ठाकुर,कुलेश्वर साहू, गुड्डू यादव व निगम अधिकारी व स्थानीय क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक, युवा एवं महिला कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

डीजल पेट्रोल में मात्र 2-2 रुपये की कमी चुनावी तुष्टीकरण : कुरैशी

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व मंत्री बदरूदीन कुरैशी ने केन्द्र सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के 4 दिन पूर्व देश की जनता को तुष्टीकरण करने के उदेश्य से केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इशारे पर पेट्रोल और डीजल की कीमत में 2-2 रूपये कम किया है।

जिस प्रकार पिछले सप्ताह से पूरे देश के राज्यों में घूम घूम कर आमजनता को तुष्टीकरण करने के उदेश्य से नरेन्द्र मोदी हर राज्यों में जाकर हजारों करोड़ो लाखों रूपये की योजनाओं की मात्र घोषणा और शिलान्यास करते जा रहे है जबकि देश में पिछले कई महिनों से डीजल और पेट्रोल का रेट बढते चला जा रहा है जबकि डीजल पेट्रोल की बढती महंगाई को देखकर केन्द्र सरकार के राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी पार्टी के राज्य सरकारों को एक्साइज डयूटी वेट कम करने के लिए निर्देश दिये केन्द्र उसके बावजूद मध्यप्रदेश राजस्थान महाराष्ट्र इस प्रकार कई राज्यों में एक्साइज डयूटी और वेट कर कम नहीं किया गया आज चुनावी घोषणा होने के 3-4 दिन पूर्व देश की जनता को गुमराह करने के उदेश्य से बढते डीजल और पेट्रोल की कीमतों को मात्र 2-2 रूपये कम करके आमजनता का तुष्टीकरण किया जा रहा है।

मनमोहन सिंह जी की सरकार 2014 में केन्द्र में सरकार थी क्रुड आइल 108 डॉलर प्रति बैरल था ऐसी स्थिति में भी पेट्रोल की कीमत 71 रूपये 51 पैसा प्रति लीटर और डीजल 57 रूपये 28 पैसा प्रति लीटर था जबकि फरवरी 2021 में मोदी सरकार में क्रुड आईल की किमत 61 डॉलर प्रति बैरल है।

उस समय दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 89.29 रूपये प्रति लीटर डीजल की किमत 79.70 रूपये प्रति लिटर था मोदी सरकार ने पिछले 6 सालों में पेट्रोल डीजल पर लगने वाली एक्साईज डयूटी कुल 12 बार बढ़ाया है लेकिन घटाया सिर्फ 2 बार है पहली बार केन्द्र सरकार ने अक्टूबर 2017 में एक्साइज डयूटी 2 रूपये घटाई थी दूसरी बार अक्टूबर 2018 में एक्साईज डयूटी 2 रूपये घटाई थी इसके अलावा केन्द्र सरकार ने हर बार एक्साइज डयूटी बढाई मई 2020 में एकसाथ पेट्रोल पर 10 रूपये और डीजल पर 13 रूपये एक्साइज डयूटी बढाई थी जिससे केन्द्र को जाने वाला पेट्रोल का एक्साइज डयूटी 32.98 और डीजल 31.83 पैसा हो गया यह सच्चाई है कि एक्साइज डयूटी मोदी सरकार द्वारा लगाई गई है आज तक पिछला रिकार्ड देख लिया जाये उतनी कभी किसी कार्यकाल में एक्साइज डयूटी नहीं लगी यूपीए सरकार में डीजल पर वेट 3.56 पैसा था जबकि अब करीब 32 रूपया है जबकि क्रुड आइल डालर कम होने के बावजूद केन्द्र की सरकार एक्साइज डयूटी वेट कर कभी कम नहीं करी आज भी केन्द्र सरकार देश की महंगाई शिक्षित बेरोजगारों की बेरोजगारी के प्रति कोई चिंता नहीं है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950